राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार 11 फरवरी 2026 वर्ष-9,अंक-19 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

असम में फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश, 2 .43 लाख नाम हटे

■ राज्य में अब 2 .49 करोड़ वोटर्स

गुवाहाटी (एजेंसी)। चुनाव आयोग (EC) ने मंगलवार को असम में हुए स्पेशल रिवीजन (SR) 2026 के तहत फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी। एउ के मुताबिक, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में 2.43 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। अब राज्य में कुल 2,49,58,139 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या 2,52,01,624 थी। स्पेशल रिवीजन प्रक्रिया के बाद लिस्ट में 2,43,485 नाम हटाए गए हैं। अब फाइनल लिस्ट में 1,24,82,213 पुरुष, 1,24,75,583 महिलाएं और 343 थर्ड-जेंडर शामिल हैं। स्पेशल रिवीजन की इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 27 दिसंबर 2025 को पब्लिश हुई थी। इस पर 27 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां करने का समय था। 22 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक पूरे राज्य में घर-घर (H2H) वेरिफिकेशन अभियान चलाया गया था। असम की 126 विधानसभा सीटों पर अगले तीन महीनों में चुनाव होने हैं। इससे पहले 27 दिसंबर 2025 को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट रोल जारी किया गया था।

भाजपा की संगीता खांडेकर बनीं चंद्रपुर नगर परिषद की मेयर

■ कांग्रेस ने लगाया हॉर्स-ट्रेडिंग का आरोप

मुम्बई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव के बाद अब मेयर को चुनने की दौड़ लगातार जारी है। कहीं मेयर चुने जा चुके है, कही अभी बाकी है, जिसकी जद्दोजहद लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज चंद्रपुर नगर पालिका में भाजपा के मेयर के चुनाव के बाद घमासान शुरू हो गया। भाजपा की पार्षद संगीता खांडेकर शिवसेना (यूबीटी) के समर्थन से मेयर चुनी गईं हैं। शिवसेना (यूबीटी) के पार्षद प्रशांत दानव डिप्टी मेयर चुने गए। इसी से परेशान होकर कांग्रेस ने पार्षद की खरीद फरोखत का आरोप लगाया है और इसके लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी, एआईएमआईएमऔर वंचित बहुजन अघाड़ी को ज़िम्मेदार ठहराया है। यह पूरा घमासान उस समय शुरू हुआ जब भाजपा ने कांग्रेस को हरा दिया। इसके लिए उसने शिवसेना (यूबीटी) के पार्षदों का समर्थन हासिल किया। कांग्रेस नेता कहा चंद्रपुर मेयर चुनाव में, इखढ को 32 वोट और कांग्रेस को 31 वोट मिले।

अब एआई जनरेटेड कंटेंट पर लगाना होगा वाटरमार्क

सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी किया आदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल (वाटरमार्क) लगाएं। ऐसी सामग्री में पहचान के लिए संकेत जरूर होने चाहिए। सरकार ने कहा कि एक बार एआई लेबल या मेटा डाटा लगाने के बाद उसे हटाया या दबाया नहीं जा सकता। सरकार ने कहा कि अब मानव निर्मित या कृत्रिम रूप से बनाई गई जानकारी को स्पष्ट रूप से पहचान योग्य लेबल (वाटरमार्क) के साथ दिखाना अनिवार्य होगा। इसमें ऑडियो, वीडियो, फोटो या ग्राफिक सहित किसी भी डिजिटल सामग्री को शामिल किया गया है, जिसे कंप्यूटर या किसी संसाधन से बनाया गया, संशोधित किया गया या बदला गया हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी यूजर ऐसी सामग्री का गलत इस्तेमाल न करे। अगर कोई यूजर गैरकानूनी, अश्लील, धोखाधड़ी या बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री बनाए या साझा करे, तो प्लेटफॉर्म्स उसे रोकने के लिए स्वचालित (ऑटोमेटेड) तकनीक का इस्तेमाल करेंगे।प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स को कम से कम हर तीन महीने में चेतावनी देनी होगी कि नियमों का उल्लंघन करने पर दंड या सजा हो सकती है। यदि कोई नियम तोड़े, तो उसका खाता निलंबित किया जा सकता है या सामग्री को हटाया जा सकता है। सरकार ने कार्रवाई की समयसीमा भी घटा दी है। पहले 36 घंटे में कार्रवाई करनी थी, अब तीन घंटे में सूचना देना अनिवार्य है।

उल्लंघन होने पर प्लेटफॉर्म्स को तुरंत उचित कार्रवाई करनी होगी। यह कदम डिजिटल मीडिया में सुरक्षा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इससे यूजर्स को यह पता चलेगा कि कौन-सी जानकारी वास्तविक है और कौन-सी कृत्रिम रूप से बनाई गई है।

सीएम योगी बोले: बाबरी ढांचा कयामत के दिन तक नहीं बनेगा

जो कानून तोड़ेगा उसे जहन्नुम मिलेगा, कायदे से रहना सीख लो

बाराबंकी (एजेंसी)। कयामत की रात कभी नहीं आएगी, इसलिए बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कभी संभव नहीं है। जो लोग कयामत के दिन का सपना देख रहे हैं, वे ऐसे ही सड़-गल जाएंगे। ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, क्योंकि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जो कानून तोड़ेगा, वो सीधे जहन्नुम में जाएगा। यह बात सीएम योगी ने मंगलवार को बाराबंकी में कही। उन्होंने कहा- ये डबल इंजन की सरकार है। हम लोगों ने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया न मंदिर। कोई संदेह है। राम को भूल जाते हैं, इसलिए भगवान राम भी उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होगी। उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ना। रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं। जो रामभक्तों पर गोली चला रहे थे, अब इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं। राम सबके हैं, इसमें भेद नहीं। कुछ अवसरवादी राम को भूल जाते हैं। योगी बाराबंकी में श्री हनुमत विराट महायज्ञ एवं श्रीरामार्चा पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। यज्ञ मंडप में आहुति दी। इस दौरान संत बलराम दास ने मखाने और लावा की माला पहनाकर योगी का स्वागत किया। इसके बाद योगी ने कहा- हम सब भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करें।

2017 से पहले कोई सुरक्षित नहीं था। पहले गरीबों की जमीन पर कब्जा हो जाता था। सरकार बदलते ही सारी अराजकता गायब हो गई। हमारी सरकार में सब सुरक्षित हैं। योगी ने कहा- बेटी सुरक्षित होगी, तो समाज अपने आप सुरक्षा का एहसास करेगा। व्यापारी सुरक्षित होगा, तो तरक्की होगी। पहले वेतन देने का पैसा नहीं होता था। आज सभी को वेतन समय पर मिल रहा। सरकार करोड़ों लोगों को पेंशन दे रही है। आज प्रदेश तरक्की कर रहा है। कहा- सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जो कानून अपने हाथ में लेगा, तो कानून उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी।\ योगी ने कहा- पहले गरीबों के घर नहीं बन पाए। मोदीजी आए, तो यूपी के 60 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिले। पहले गांवों में बिजली नहीं थी, सड़कों पर गंदगी थी। अब घर-घर शौचालय बन गए। साफ पानी मुहैया कराया जा रहा है। पहले बिजली नहीं मिलती थी। कुछ चुनिंदा जिलों को ही बिजली मिलती थी। अब सभी 75 जिलों को बिजली मिल रही। पहले की सरकारों में शौचालय नहीं थे। लोगों को मुंह बंद करके खेतों में जाना पड़ता था।

मोदी का प्लेन असम में हाईवे पर उतर सकता है

■ यहां पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी एयरस्ट्रिप बनी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को असम के मोरान में हाईवे पर बनी इमरजेंसी एयरस्ट्रिप पर उतर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि ऐसा होता है तो यह पूर्वोत्तर भारत में पहली बार होगा जब किसी पीएम का प्लेन पारंपरिक एयरपोर्ट की बजाय हाईवे पर लैंड करेगा। यह एयरस्ट्रिप नेशनल हाईवे (NH) 127 के डिब्रूगढ़-मोरान हिस्से पर बनाई गई है। पीएम की मौजूदगी में राफेल और सुखोई लड़ाकू विमान एक स्पेशल एरियल डेमो करेंगे। इसमें विमान हाईवे से ही लैंडिंग और टेकऑफ दिखाएंगे। डेमो करीब 30-40 मिनट का होगा। असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उम्मीद जताई कि पीएम मोदी फाइटर एयरक्राफ्ट में मोरन हाईवे पर उतरेंगे। मुख्य सचिव रवि कोटा ने कहा कि 14 फरवरी को प्रधानमंत्री 4.4 के एयरस्ट्रिप के उद्घाटन के लिए मोरन आएंगे। यह कार्यक्रम भारत की आपदा तैयारी, पूर्वोत्तर विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को दर्शाएगा। पीएम की यात्रा सिविल-मिलिट्री दोहरे उपयोग वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और डेमो एयरस्ट्रिप की क्षमता पर फोकस करेगी। राफेल और सुखोई भारतीय वायुसेना के प्रमुख लड़ाकू विमान हैं। मोरान एयरस्ट्रिप NH-127 के 4.4 किलोमीटर लंबे हिस्से पर बनाई गई है। यह भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) है, जो सेना और सिविल विमानों दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ELF का मतलब है कि युद्ध या आपात स्थिति में विमान हाईवे पर उतर या उड़ान भर सकते हैं। इससे सड़क का दोहरा फायदा होता है। रोजमर्रा की ट्रैफिक के साथ-साथ सैन्य जरूरतों के लिए। यह एयरस्ट्रिप पूर्वोत्तर की रणनीतिक महत्व को बढ़ाती है, क्योंकि यह क्षेत्र चीन की सीमा से सटा है। सरकार ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य जगहों पर भी ELF बनाए हैं।

पेंगुइन का दावा: नरवणे की किताब पब्लिश नहीं हुई: पूर्व सेना प्रमुख ने पब्लिकेशन की पोस्ट शेयर की

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी (Four Stars of Destiny)' पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कहा कि किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। इसका कोई हिस्सा सार्वजनिक नहीं किया गया। कंपनी ने कहा कि पब्लिशिंग के सभी राइट्स हमारे पास हैं। अब तक किताब की न तो कोई छपी हुई कॉपी आई है और न ही डिजिटल कॉपी सामने आई है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा- या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं, या पेंगुइन कंपनी। वहीं कंपनी के बयान को पूर्व आर्मी चीफ ने पर रीपोस्ट किया। उन्होंने लिखा- यह है बुक पर स्थिति। दरअसल, कंपनी की सफाई इसलिए आई क्योंकि किताब की अनअथॉराइज्ड कॉपियों के लीक और ऑनलाइन सकुर्लेशन का दावा सामने आया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। यह कार्रवाई अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज फोरम पर मिली जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें दावा किया गया था कि किताब की प्री-प्रिंट कॉपी सकुर्लेट हो रही है। राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा के बाहर कहा- एमएम नरवणे ने X पर पोस्ट किया है, हेलो दोस्तों, मेरी किताब अब अवेलेबल है। लिंक फॉलो करें। हैप्पी रीडिंग। या तो एमएम नरवणे झूठ बोल रहे हैं, या पेंगुइन झूठ बोल रहा है। मैंने आर्मी चीफ पर विश्वास करना चुना। उन्होंने आगे कहा कि क्या आप एमएम नरवणे के बजाय पेंगुइन पर विश्वास करेंगे? किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो सरकार के लिए असुविधाजनक हैं।

टी20 विश्वकप में परिवार साथ नहीं ले जा सकेंगे भारतीय खिलाड़ी

नई दिल्ली (एजेंसी)। टी20 विश्वकप 2026 में भारतीय टीम के बेहतर प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई ने सख्त कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीसीसीआई ने अपनी सख्त नीतियों पर कायम रहते हुए टी20 वर्ल्ड कप अभियान के दौरान खिलाड़ियों के परिवारों और पार्टनर्स को उनके साथ रहने से रोक दिया है।सूत्रों के मुताबिक, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने मांग की थी कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनके परिवारों को भी साथ रहने की अनुमति दी जाए। हालांकि, खबर है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस मांग को फिलहाल ठुकरा दिया है। बोर्ड की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी आना बाकी है।बता दें, टी20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम ग्रुप स्टेज के तीन मुकाबले भारत में ही खेलने वाली है। बीसीसीआई के नियम के मुताबिक 45 दिनों से ज्यादा चलने वाली सीरीज या टूर्नामेंट के लिए परिवार के सदस्य खिलाड़ियों के साथ 14 दिनों तक रह सकते हैं, जबकि छोटे टूर के लिए यह लिमिट घटाकर सिर्फ सात दिन कर दी गई है।

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश

ओम बिरला का लोकसभा में ना जाने का फैसला, 9 मार्च को प्रस्ताव पर चर्चा होगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। विपक्ष ने मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश कर दिया। इसमें 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ओम बिरला अब लोकसभा नहीं जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद ही वह स्पीकर की चेयर संभालेंगे। एजेंसी के मुताबिक विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। 13 फरवरी को बजट सत्र के वर्तमान सेशन का आखिरी दिन है। इसके बाद 8 मार्च से सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। इससे पहले बजट सत्र के 10वें दिन संसद दो बार स्थगित हुई। दोपहर 2 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू हो सकी। शशि थरूर ने बजट पर चर्चा की शुरूआत की। राहुल का यह बयान पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के उस क्लैरिफिकेशन के बाद आया, जिसमें कहा गया कि नरवणे की किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। पब्लिशिंग के सभी राइट्स हमारे पास हैं। पेंगुइन कंपनी ने कहा- अब तक किताब की न तो कोई छपी हुई और न ही डिजिटल कॉपी सामने आई है। हमारी तरफ से किताब का कोई भी हिस्सा कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। कंपनी की सफाई इसलिए आई, क्योंकि बुक की अनअथॉराइज्ड कॉपियों के लीक और ऑनलाइन सकुर्लेशन का दावा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। दरअसल, राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ की किताब लेकर लोकसभा पहुंचे थे। पूरा विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि उन्हें सदन में बोलने दिया जाए। राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 3 फरवरी तक देश भर के आदिवासी बहुल इलाकों में 6.83 करोड़ से ज्यादा लोगों की सिकल सेल एनीमिया के लिए स्क्रीनिंग की गई है। इनमें से लगभग 2.38 लाख लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड पाए गए, जबकि 19.32 लाख से ज्यादा लोगों की पहचान कैरियर के तौर पर हुई। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने संसद में कहा कि बीजेपी को तीन बार बंगाल में हार देखनी पड़ी है। चौथी बार भी देखेंगे। सरकार ने बंगाल को बेहद कम फंड दिया। हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार एजेंसी से हमे परेशान कर रही है लेकिन हम इसका भी जवाब देंगे, आप फाइल सीज रहे हैं, बजट रोक रहे हैं लेकिन बंगाल आगे बढ़ेगा। बंगाल के लेबर को लेबर नहीं सस्पेक्ट की तरह देखा जा रहा है। बनर्जी ने कहा कि इन्हें मणिपुर पहुंचने में 2 साल लग गए। ये हर जगह गए लेकिन मणिपुर नहीं। कुछ चीजें बजट से ऊपर होती हैं पर आप ये नहीं समझेंगे। ये भूल गए हैं कि संविधान की शुरूआत हम भारत के लोग से होती है। उन्होंने कहा कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। संविधान आपको रोकेगा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि देश की जनता को हर चीज में टैक्स देना पड़ा रहा है, जन्म, पढ़ाई, लिखाई, खाने पीने, मरने तक पर टैक्स देना पड़ रहा है। मरने के बाद अगरबत्ती पर भी टैक्स देना पड़ रहा है। यही पूरे बजट का सार है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सरकारी कंपनियों को ये सरकार बेच रही है।

मणिपुर के उखरुल में पांच दिन के लिए इंटरनेट बंद

उपद्रवियों ने 25 घर और चार सरकारी क्वार्टर फूंके, जिले में कर्फ्यू लागू

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर में नई सरकार बनने के एक हफ्ते के भीतर ही हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने उखरुल जिले के लितान सरेइखोंग गांव में 25 घर और चार सरकारी क्वार्टर में आग लगा दी। हिंसा के बाद पूरे जिले में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। 10 फरवरी की सुबह 11:30 बजे से अगले पांच दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तांगखुल और कुकी जनजातियों के बीच हिंसक झड़प के बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्स मौजूद हैं। हिंसा की शुरूआत 7 फरवरी की शाम लितान सरेइखोंग में हुए एक शराब के नशे में झगड़े से हुई थी, जिसमें तांगखुल नागा समुदाय के स्टर्लिंग नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी। उखरुल जिले के लितान इलाके के आसपास गांवों में उपद्रवियों ने कई घरों में आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि हिंसा के दौरान राइफल से गोलियां भी चलाई गईं। इलाके में दहशत फैलने के बाद कर्फ्यू लागू किया गया। स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है, लेकिन भारी सुरक्षा तैनाती के चलते काफी हद तक कंट्रोल में है। तनाव बढ़ने की आशंका के बीच लोगों ने बिना किसी प्रशासनिक मदद के अपने स्तर पर ही घर छोड़ना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि लितान थाना पुलिस ने लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की और कानून-व्यवस्था बनाए रखी है। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में बीएसएफ, सीआरपीएफ और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है, जबकि अतिरिक्त सुरक्षा बल भी भेजे गए हैं। इंफाल से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित लितान एक छोटा व्यावसायिक कस्बा है, जहां तांगखुल नागा और कुकी दोनों समुदाय रहते हैं। यह आसपास के गांवों के लिए व्यापारिक केंद्र के रूप में काम करता है। सुरक्षा और समन्वय के लिए लितान पुलिस स्टेशन में जॉइंट कंट्रोल रूम बनाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस ने बताया कि पिछले 24 घंटों में पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था सामान्य रही। संवेदनशील और सीमावर्ती इलाकों में सर्च ऑपरेशन और एरिया डॉमिनेशन जारी हैं। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 115 नाके और चेकपोस्ट लगाए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर जरूरी सामान लदे 306 वाहनों को सुरक्षा काफिले के साथ सुरक्षित पहुंचाया गया।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

दीनदयाल उपाध्याय: राष्ट्रवादी चिंतक और सजग पत्रकार

(लेखक- हर्षवर्धन पान्डे)

(11 फरवरी पुण्यतिथि पर विशेष)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक भारतीय विचारक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री,लेखक, पत्रकार, संपादक थे। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी एक दौर में रहे। ब्रिटिश शासन के दौरान इन्होंने भारत द्वारा पश्चिमी धर्म निरपेक्षता का विरोध किया। उन्होनें लोकतंत्र की अवधारणा को सरलता से स्वीकार किया लेकिन पश्चिमी कुलीनतंत्र, शोषण और पूंजीवादी मानने से साफ़ इंकार कर दिया। पंडित जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन जनता की सेवा में लगा दिया। भारतीय पत्रकारिता ने सदैव राष्ट्रवाद को पल्लवित करने का निर्वहन किया है। पत्रकारिता में राष्ट्रवादी स्वर को गति देने वाले पत्रकारों में पं. दीनदयाल उपाध्याय का नाम आदर के साथ लिया जाता है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अनेक नेताओं ने पत्रकारिता के प्रभावों का उपयोग अपने देश को स्वतंत्रता दिलाकर राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए किया। विशेषकर हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषायी पत्रकारों में खोजने पर भी ऐसा सम्पादक शायद ही मिले जिसने अर्थोपार्जन के लिए पत्रकारिता का अवलम्बन किया हो।

दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितम्बर, 1916, नगला चन्द्रभान, मथुरा, उत्तर प्रदेश में एक मध्यम वर्गीय प्रतिष्ठित हिंदू परिवार में हुआ था। उनके परदादा का नाम पंडित हरिराम उपाध्याय था, जो एक प्रख्यात ज्योतिषी थे। उनके पिता का नाम श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय तथा मां का नाम रामप्यारी था। उनके पिता जलेसर में सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में कार्यरत थे। दीनदयाल ने कम उम्र में ही अनेक उतार-चढ़ाव देखा, परंतु अपने दृढ़ निश्चय से जिन्दगी में आगे बढ़े। उन्होंने सीकर से हाईस्कूल की परीक्षा पास की जन्म से बुद्धिमान और उज्ज्वल प्रतिभा के धनी दीनदयाल को स्कूल और कालेज में अध्ययन के दौरान कई स्वर्ण पदक और प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। दीनदयाल इण्टरमीडिएट की पढ़ाई के लिए 1935 में पिलानी चले गए। 1937 में इण्टरमीडिएट बोर्ड के परीक्षा में बैठे और न केवल समस्त बोर्ड में सर्वप्रथम रहे वरन सब विषयों में विशेष योग्यता के अंक प्राप्त किए। बिडला कॉलेज का यह प्रथम छात्र था, जिसने इतने सम्मानजनक अंको से परीक्षा पास की थी। सीकर महाराजा के समान ही घनश्याम दास बिड़ला ने एक स्वर्ण पदक, 10रू मासिक छात्रवृत्ति तथा पुस्तकों आदि के खर्च के लिए 250 रू प्रदान किए। सन 1939 में सनातन धर्म कॉलेज, कानपुर से प्रथम श्रेणी में बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। एम.ए. अंग्रेजी साहित्य में करने के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में प्रवेश लिया। इसके पश्चात उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की लेकिन आम जनता की सेवा की खातिर उन्होंने इसका परित्याग कर दिया।

दीनदयाल उपाध्याय की पत्रकारिता में भी अग्रणी भूमिका रही है। अपने राष्ट्रवाद के विचारों को जनमानस तक प्रेषित करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ने पत्रकारिता को माध्यम बनाया था। पत्रकारिता किस प्रकार से जनमत निर्माण करने में सहायक होती है, यह दीनदयाल जी ने बखूबी समझा था। एकात्म मानववाद के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय ने गांधी के विचार को पुन:व्याख्यायित करते हुए अंत्योदय की बात की। दीनदयाल जी ने राष्ट्रहित व चिंतन के विचारों को पत्रकारिता के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक कुशल पत्रकार और बेहतर संचारक थे। अपनी विचारधारा को पुष्ट करने के लिए पत्रों का संपादन, प्रकाशन, स्तंभ लेखन, पुस्तक लेखन उनकी रुचि का विषय था। उन्होंने लिखने के साथ-साथ बोलकर भी एक प्रभावी संचारक की भूमिका का निर्वहन किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लोक कल्याण को ही पत्रकारिता का प्रमुख आधार माना। दीनदयाल के पास समाचारों का न्यायवादी एवं समन्वयवादी दृष्टिकोण था। उनके लेखों, उपन्यासों व नियमित कॉलमों में निष्पक्ष आलोचना, उचित शब्दों का प्रयोग और सत्यपरक खबरों को ही मानवता के अनुकूल मिलता है। राष्ट्र भक्ति को पल्लवित करने की भावना को साकार स्वरूप देने का श्रेय उंनकी पत्रकारिता को भी जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को साहित्य से एक अलग ही लगाव था शायद इसलिए दीनदयाल उपाध्याय अपनी तमाम ज़न्दिगी साहित्य से जुड़े रहे। उनके हिंदी और अंग्रेजी के लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। साहित्य से लगाव इतना की उन्होंने केवल एक बैठक में ही चंद्रगुप्त नाटक लिख डाला था। भारत विभाजन के दौर में भयानक रक्तपात हुआ। देश, भारत को एक राष्ट्र मानने तथा भारत को द्विराष्ट्र मानने वाले में बंट गया। इसी हिंसाचार ने महात्मा गांधी को भी लील लिया। उनकी जघन्य हत्या हुई। देश के विभाजन की विभीषिका ने दीनदयाल जी को बहुत आहत किया। उन्होनें इस पर प्रखरतापूर्वक अपना पक्ष रखा। पंडित दीनदयाल के अनुसार अखण्ड भारत देश की भौगोलिक एकता का ही परिचायक नहीं अपितु जीवन के भारतीय दृष्टिकोण का परिचायक है जो अनेकता में एकता का दर्शन करता है। अत: हमारे लिए अखण्ड भारत राजनैतिक नारा नहीं है, बल्कि यह तो हमारे संपूर्ण जीवनदर्शन का मूलाधार है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय को साहित्य से एक अलग ही लगाव था शायद इसलिए दीनदयाल उपाध्याय अपनी तमाम ज़न्दिगी साहित्य से जुड़े रहे। उनके हिंदी और अंग्रेजी के लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। साहित्य से लगाव इतना की उन्होंने केवल एक बैठक में ही चंद्रगुप्त नाटक लिख डाला था। भारत विभाजन के दौर में भयानक रक्तपात हुआ। देश, भारत को एक राष्ट्र मानने तथा भारत को द्विराष्ट्र मानने वाले में बंट गया। इसी हिंसाचार ने महात्मा गांधी को भी लील लिया।

अखंड भारत की अवधारणा से संबंधित ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विश्लेषणार्थ उपाध्याय ने अखण्ड भारत क्यों? नाम की पुस्तिका लिखी, जिसमें उन्होंने प्राचीन भारत साहित्य के संदर्भित करते हुए भारत में युगों से चली आयी उस सांस्कृतिक एवं राजनैतिक परम्परा का उल्लेख किया है जो भौगोलिक भारत को एक एकात्म राष्ट्र के रूप में विकसित करने में समर्थ हुई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्पष्ट मत था कि भारत माता को खण्डित किये बिना भी भारत की आजादी प्राप्त की जा सकती थी और भारत माता को परम वैभव तक पहुँचाने में हम अधिक तीव्रगति से सफल हो सकते थे किंतु पंडित नेहरू और जिन्ना के सत्ता के लालच और अंग्रेजों की चाल में आ जाने से भारतवासियों का यह सपना पूर्ण नहीं हुआ और खण्डित भारत को आजादी मिली। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्तिवाद अधर्म है। राष्ट्र के लिए काम करना धर्म है। दीनदयाल उपाध्याय बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उनमें एक कुशल शिक्षाविद, अर्थचिंतक, संगठनकर्ता, राजनीतिज्ञ, लेखक व पत्रकार सहित अनेक गुण थे। यह बात अलग है कि उन्हें लोग एकात्म मानववाद के प्रणेता के रूप और एक संगठन के कुशल सेवी के रूप में ज्यादा जाना जाता है। उनमें लेखन और संपादन का अद्भुत कौशल विद्यमान था। उनकी गणना उस दौर के प्रतिष्ठित पत्रकारों में भी जाती थी। उनके पत्रकारीय व्यक्तित्व में पत्रकारिता का आदर्शवाद समाहित था। आजादी के समय में अनेक नेताओं ने पत्रकारिता के प्रभावों का उपयोग अपने देश को आजादी दिलाकर राष्ट्र के पुनर्निर्माण और जनजागरण के लिए समर्पित किया। दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व में एक संपादक के सभी पत्रकारीय गुण दिखाई पड़ते थे। दीनदयाल उपाध्याय मानते थे कि पत्रकारिता एक मिशनरी संकल्प है जिसे पूरी लगन एवं तल्लीनता से करनी चाहिए। समाजहित की पत्रकारिता में व्यावसायिक पत्रकार का कोई स्थान नहीं होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने व्यस्त राजनीतिक जीवन से अनेक वर्षों तक आरगेनाइजर, राष्ट्रधर्म, पांचजन्य में ''पॉलिटिकल डायरी'' नामक स्तम्भ के अंतर्गत तत्कालीन राजनीतिक-आर्थिक घटनाक्रम पर गम्भीर विवेचनात्मक टिप्पणियां लिखते रहे। दीनदयाल जी की टिप्पणी सामयिक और बहुत पते की होती थी। सन 1947 में पंडित दीनदयाल ने राष्ट्रधर्म प्रकाशन लिमिटेड की स्थापना की जिसके अंतर्गत स्वदेश, राष्ट्रधर्म एवं पांचजन्य नामक पत्र प्रकाशित होते थे। दीनदयाल ने 'पांचजन्य', 'राष्ट्रधर्म' एवं 'स्वदेश' के माध्यम से राष्ट्रवादी जनमत निर्माण करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था।

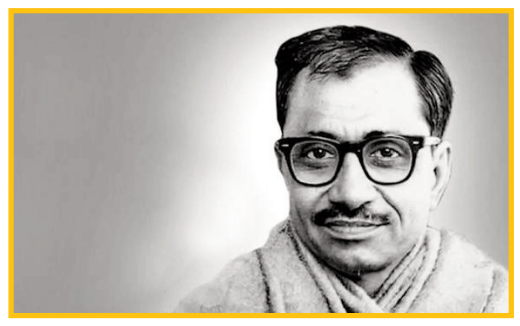

पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा एकात्म मानववाद का विकल्प एवं अंत्योदय का विचार उस कालखंड में दिया गया जब देश में समाजवाद, साम्यवाद जैसी आयातित विचारधाराओं का बोलबाला था। भारत में भारतीयता को पुनर्जीवित करने वाली विचारधारा की बजाय समाजवाद एवं साम्यवाद जैसी आयातित विचारधाराओं का बोलबाला होना भारतीयता के लिए अनुकूल नहीं था। पंडित जी ने भारत की समस्या को भारत के सन्दर्भों में समझकर उसका भारतीयता के अनुकूल समाधान देने की दिशा में एक युगानुकुल प्रयास किया। दीनदयाल जी ने अपने चिन्तन में आम मानव से जुड़ी जिन चिंताओं और समाधानों को समझाने का प्रयास आज से दशकों पहले किया था। सही मायनों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पत्रकारिता को भी इसी दृष्टि से एक नई दिशा दी। वे स्वयं कभी संपादक या औपचारिक संवादाता नहीं रहे। उन्होंने संपादकों और संवाददाताओं का सुखद सानिध्य प्राप्त किया। तभी संपादक व पत्रकार उन्हें सहज ही अपना मित्र एवं मार्गदर्शक मानते थे। पत्रकार के नाते पंडित जी का योगदान अनुकरणीय था। दीनदयाल जी उस युग की पत्रकारिता का प्रतिनिधित्व करते थे जब पत्रकारिता एक मिशन होने के कारण आदर्श थी व्यवसाय नहीं थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अनेक नेताओं ने पत्रकारिता के प्रभावों का उपयोग अपने देश को स्वतंत्रता दिलाकर राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए किया। ऐसा सम्पादक शायद ही मिले जिसने अर्थोपार्जन के लिए पत्रकारिता का अवलंबन किया हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि पत्रकारिता करते समय राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और स्वदेश के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में जो मूल्य और मानदंड स्थापित किया उसकी दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती। दीनदयाल उपाध्याय का पत्रकारीय चिंतन राष्ट्रवादी और भारतीय जीवन मूल्यों की विचारधारा से जुड़ता है। पत्रकारिता के आधार पर उन्होंने राष्ट्र को समझने तथा भारतीय अस्मिता को लोगों तक पहुंचाने का गंभीर प्रयास किया है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं)

संपादकीय

बंगाल में एसआईआर, घुसपैठियों को निष्कासित करने का काम हर हाल में किया जाए

यह ठीक नहीं कि भारत सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की बातें तो बार-बार करती है, लेकिन इसके लिए कोई प्रभावी अभियान नही चलाती। समझना कठिन है कि मतदाता सूचियों में संशोधन-परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर अर्थात एनआरसी को क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआइआर की प्रक्रिया के तहत जारी मसौदा सूची से 58 लाख नाम कटने के बाद जिस तरह करीब पांच लाख लोग सुनवाई प्रक्रिया में नहीं पहुंचे, उससे यह लगता है कि नाम कटने वालों का आंकड़ा 63 लाख तक पहुंच सकता है। चूंकि एसआइआर से जुड़े दावों और आपत्तियों पर सुनवाई की समयसीमा बढ़ा दी गई है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह बंगाल में लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से कटे हैं, उसी तरह कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसा ही हुआ है। आम तौर पर ये वे लोग हैं, जो अन्यत्र चले गए अथवा अपने पते-ठिकाने पर नहीं रह रहे या फिर जिनका निधन हो गया है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बिहार में भी इसी कारण अच्छी खासी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर हुए थे। अब यदि बंगाल में भी ऐसा होने जा रहा है तो ऐसे किसी नतीजे पर पहुंचने का कोई मतलब नहीं कि जानबूझकर लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने इसी आरोप के साथ पहले तो धरने-प्रदर्शन की राजनीति की, फिर अपना पक्ष रखने वकील की हैसियत से स्वयं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। इसका उद्देश्य यह संदेश देना था कि चुनाव आयोग बंगाल के लोगों के साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन इसमें वे नाकाम रहीं। आखिर जब सुप्रीम कोर्ट एसआइआर से जुड़ी विसंगतियों पर निगाह रख रहा है और इस संदर्भ में आवश्यक आदेश-निर्देश भी दे रहा है, तब फिर मतदाता सूचियों को शुद्ध करने की इस प्रक्रिया के विरोध का कोई औचित्य नहीं। यह विचित्र ही है कि ममता बनर्जी एसआइआर में विसंगतियों को इंगित करने के बजाय यह चाह रही हैं कि यह प्रक्रिया हो ही ना। चुनाव आयोग को समय-समय पर एसआइआर की प्रक्रिया करनी ही चाहिए, क्योंकि इसी से मतदाता सूचियां दुरुस्त होंगी और दुरुस्त मतदाता सूचियां निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव की बुनियाद हैं। बंगाल में एसआइआर का विरोध इसलिए हो रहा है, क्योंकि इससे अवैध बांग्लादेशियों के नाम कट सकते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, लेकिन भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि एसआइआर के जरिये बांग्लादेशी घुसपैठिये चिह्नित हों तो उन्हें निष्कासित करने का काम हर हाल में किया जाए। यह ठीक नहीं कि भारत सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की बातें तो बार-बार करती है, लेकिन इसके लिए कोई प्रभावी अभियान नही चलाती। समझना कठिन है कि मतदाता सूचियों में संशोधन-परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर अर्थात एनआरसी को क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है?

लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास!

(लेखक -डॉ श्रीगोपाल नारसन)

विपक्ष के 128 लोकसभा सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंप दिया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बताया कि उन्होंने नियम 94सी के तहत लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को卐बोलने की इजाजत नहीं देने卐, साथ ही कांग्रेस की महिला सांसदों पर सदन में अनुचित स्थिति पैदा करने के आरोपों पर विपक्ष अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए यह प्रस्ताव लाया है।लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई, कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश और सांसद मोहम्मद जावेद तथा अन्य कई सांसद नोटिस सौंपने वालो में शामिल है।लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के मानदंडों के नियम 198 के अनुसार, विपक्ष को लोकसभा में मतदान से पहले अविश्वास प्रस्ताव के अपने अनुरोध के लिए औचित्य प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया लोकसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन प्रणाली के नियम 198 (1) से नियम 198 (5) तक के तहत पूरी की जाती है।इस प्रक्रिया के तहत नियम 198 (1) (क) के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद को पहले स्पीकर के जरिये सदन की अनुमति लेनी पड़ती है।सदन की अनुमति के लिए नियम 198 (1) (ख) के मुताबिक, प्रस्ताव की जानकारी सुबह 10 बजे से पहले लोकसभा के महासचिव को देनी पड़ती है।नियम 198 (2) के तहत प्रस्ताव के साथ सांसद को 50 सांसदों के समर्थन वाले हस्ताक्षर दिखाने होते हैं।नियम 198 (3) के तहत लोकसभा अध्यक्ष से प्रस्ताव को अनुमति मिलने के बाद उस पर चर्चा का दिन तय होता है। चर्चा प्रस्ताव पेश होने के 10 दिन के अंदर करानी होती है।नियम 198 (4) के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के अंतिम दिन लोकसभाध्यक्ष वोटिंग कराते हैं और उस आधार पर फैसला होता है।नियम 198(5) के तहत लोकसभा अध्यक्ष को टिप्पणी के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार है। यदि प्रस्ताव सदन द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है ।अब तक लोक सभा में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं।लोक सभा में सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव अगस्त 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ जे बी कृपलानी ने पेश किया था। लेकिन विपक्ष सरकार गिराने में नाकाम हो गया था, क्योंकि इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े और विरोध में 347 वोट पड़े थे।लेकिन सन 1978 में लाये गए अविश्वास प्रस्ताव ने मोरारजी देसाई सरकार को गिरा दिया था।अब तक सबसे ज्यादा 4 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड माकपा सांसद ज्योतिर्मय बसु के नाम है। उन्होंने अपने चारों प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ रखे थे।सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाली भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार रही है। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ 15 अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गये थे।इसके अलावा पी॰ वी॰ नरसिम्हा राव और लाल बहादुर शास्त्री की सरकारों ने तीन-तीन बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था।पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार इंदिरा गाँधी सरकार और दूसरी बार पी॰ वी॰ नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था ।संयोग की बात है कि अटल सरकार के खिलाफ भी दो बार सन1996 व सन1998 अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था और वे दोनों बार हार गये थे।सन

2018 में नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था,लेकिन यह प्रस्ताव गिर गया था।

लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला पर आरोप हैं कि वो विपक्ष के साथ भेदभाव करते हैं और सांसदों को बोलने का मौका कम देते हैं।हालांकि ये पहली बार नहीं है, जब किसी लोकसभाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा हो। संसद के इतिहास में कई बार ऐसा हो चुका है।

अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संसदीय परंपरा का ही एक हिस्सा है। जब भी विपक्ष को सरकार या फिर लोकसभाध्यक्ष पर भरोसा नहीं होता है तो उन्हें हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। लोकसभाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 94(सी) के तहत लाया जाता है, इसे मोशन ऑफ रिमूवल कहा जाता है।इसके तहत लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। वोटिंग में बहुमत मिलने पर अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार सन1954 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष मावलंकर के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था। सोशलिस्ट पार्टी के नेता विग्नेश्वर मिसिर ये प्रस्ताव लाए थे।इस प्रस्ताव पर करीब दो घंटे तक चर्चा हुई थी, हालांकि बाद में उसे खारिज कर दिया गया। इस प्रस्ताव को जवाहर लाल नेहरू ने सदन की गरिमा का सवाल बताया था।

सन1954 के बाद लोकसभाध्यक्ष के खिलाफ दूसरा प्रस्ताव सन 1966 में लाया गया।लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह के खिलाफ ये प्रस्ताव था।वहीं तीसरी बार सन1987 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये प्रस्ताव तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के खिलाफ लाया गया था।पिछले तमाम प्रस्तावों की तरह ये अविश्वास प्रस्ताव भी खारिज हो गया था।अब देखना यह है कि यह अविश्वास प्रस्ताव कितना चल पाता है।इससे लोकसभाध्यक्ष की कुर्सी जाती है या फिर यह प्रस्ताव धड़ाम गिरता है।फिलहाल तो संख्या बल देखते हुए ऐसा नही लगता कि ओम बिरला की कुर्सी जाएगी,बाकी आने वाला वक्त बताएगा।

(लेखक राजनीतिक चिंतक व वरिष्ठ पत्रकार है)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

दुखी चित्त के लक्षण हैं उत्सव

दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं- एक वे जो अपने को नया करने का राज खोज लेते हैं, और एक वे जो अपने को पुराना बनाए रखते हैं और चीजों को नया करने में लगे रहते हैं। भौतिकवादी और आध्यात्मवादी में एक ही फर्क है। आध्यात्मवादी रोज अपने को नया करने की चिंता में संलग्न है। क्योंकि उसका कहना यह है कि अगर मैं नया हो गया तो इस जगत में मेरे लिए कुछ भी पुराना न रह जाएगा। क्योंकि जब मैं ही नया हो गया तो पुराने का स्मरण करने वाला भी न बचा, पुराने को देखने वाला भी न बचा, हर चीज नई हो जाएगी। और भौतिकवादी कहता है कि चीजें नई करो, क्योंकि स्वयं के नए होने का तो कोई उपाय नहीं है। नया मकान बनाओ, नई सड़कें लाओ, नए कारखाने, नई सारी व्यवस्था करो। उत्सव हमारे दुखी चित्त के लक्षण हैं। चित्त दुखी है वर्ष भर, एकाध दिन हम उत्सव मना कर खुश हो लेते हैं। वह खुशी बिल्कुल थोपी गई होती है। क्योंकि कोई दिन किसी को कैसे खुश कर सकता है? दिन! अगर कल आप उदास थे और कल मैं उदास था, तो आज दिवाली हो जाए तो मैं खुश कैसे हो जाऊंगा? हां, खुशी का भ्रम पैदा करुंगा। दीये, पटाके, फुलझड़ियां और रोशनी धोखा पैदा करेंगी कि आदमी खुश हो गया। लेकिन ध्यान रहे, जब तक दुनिया में दुखी आदमी हैं, तभी तक दिवाली है। जिस दिन दुनिया में खुश लोग होंगे उस दिन दिवाली नहीं बचेगी, क्योंकि रोज ही दिवाली जैसा जीवन होगा। जब तक दुनिया में दुखी लोग हैं तब तक मनोरंजन के साधन हैं। जिस दिन आदमी आनंदित होगा उस दिन मनोरंजन के साधन एकदम विलीन हो जाएंगे। कभी यह सोचा न होगा कि अपने को मनोरंजित करने वही आदमी जाता है जो दुखी है। इसलिए दुनिया जितनी दुखी होती जाती है उतने मनोरंजन के साधन हमें खोजने पड़ रहे हैं। चौबीस घंटे मनोरंजन चाहिए, क्योंकि आदमी दुखी होता चला जा रहा है। हम समझते है कि जो आदमी मनोरंजन की तलाश करता है, बड़ा प्रफुल्ल आदमी है। ऐसी भूल में मत पड़ जाना। सिर्फ दुखी आदमी मनोरंजन की खोज करता है। और सिर्फ दुखी आदमी ने उत्सव ईजाद किए हैं। पुराने पड़ गए चित्त में, जिसमें धूल ही धूल जम गई है; वह नए दिन, नया साल, इन सबको ईजाद करता है। और धोखा पैदा करता है थोड़ी देर। कितनी देर नया टिकता है? कल फिर पुराना दिन शुरू हो जाएगा। लेकिन एक दिन के लिए हम अपने को झटका देकर जैसे झाड़ देना चाहते हैं सारी राख को, सारी धूल को। उससे कुछ होने वाला नहीं है।

विचार मंथन

अमेरिका की 74 फ़ीसद आबादी पर रोज़ी- रोटी का संकट

(लेखक- सनत जैन)

पूंजीवादी देश अमेरिका जो दुनिया के देशों को समृद्धि और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है वह अपने ही नागरिकों को दो टाइम का भोजन नहीं दे पा रहा है। अमेरिका का मध्यम वर्ग गरीब हो रहा है। सारी दुनिया में अमेरिका की जो तस्वीर दिखाई जाती है, ठीक उसके विपरीत हालिया सर्वे मे एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने अमेरिका की कलई खोल कर रख दी है। आमतौर पर चमकदार इमारतों, शेयर बाज़ार और वैश्विक ताक़त की आड़ में अमेरिका अपनी वास्तविकता को छिपा देता है। सर्वे के अनुसार अमेरिका की करीब 74 प्रतिशत आबादी रोज़ी-रोटी के गंभीर संकट से जूझ रही है। यह संकट केवल गरीबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मिडिल क्लास और युवा वर्ग पर इसकी सबसे बड़ी मार पड़ी है। अमेरिका में हालात ये हैं, लोग बिजली, गैस, पानी जैसी बुनियादी जरूरत के मासिक बिल तक अदा नहीं कर पा रहे हैं। किराना, किराया और स्वास्थ्य खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सर्वे के अनुसार 10 में से 9 अमेरिकी मानते हैं, पूरा अमेरिका 'कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस' में फंस गया है। सर्वे में 10 में से 8 लोगों ने माना है, पिछले एक साल में महंगाई तेजी के साथ बढ़ी है। जिसके कारण उनका नियमित जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पिछले 1 साल में जिस तरह से सरकार की नीतियां हैं, उसने आम आदमी का जीवन दूभर कर दिया है। सबसे चिंताजनक स्थिति अमेरिका मे युवाओं की है। महंगाई और बेरोजगारी के चलते युवा वर्ग में गुस्सा, असंतोष और निराशा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अमेरिका का मध्यम वर्ग टैक्स रिफंड से जो राशि मिलती थी उसका उपयोग छुट्टियों, मनोरंजन या ख़रीदारी के लिए करता था। अब टैक्स रिफंड से जो राशि मिलती है, उसका उपयोग पेट भरने और कर्ज़ चुकाने के लिए करना पड़ रहा है। सर्वे के अनुसार 73 प्रतिशत लोगों ने माना है, टैक्स रिफंड अब जीवन यापन के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। 60 प्रतिशत लोगों ने रिफंड जल्दी देने की बात कही है। टैक्स रिफंड में देरी होने से खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। जेन-जी के लिए यह संकट और भी गहरा है। करीब 74 प्रतिशत युवा रिफंड नहीं मिलने पर आपात ज़रूरतें भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका के इस आर्थिक दबाव का सीधा असर सभी वर्गों पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका से आंतरिक पलायन शुरू हो गया है। लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य यहां तक कि यूरोपीय देशों में भाग रहे हैं। जहां वह वर्षों से रह रहे थे, वहां अब उनका गुज़ारा संभव नहीं हो पा रहा। सर्वे बताता है कि जेन-जी के लगभग 50 प्रतिशत युवा तथा कुल आबादी के 38 प्रतिशत अमेरिकी नागरिक आर्थिक कारणों से ठिकाना बदल चुके हैं। यह पलायन की स्थिति उन्हें जड़ों से काटने की प्रक्रिया मानी जा रही है। विडंबना यह है, जिन राज्यों को 'अफोर्डेबल अमेरिका' कहा जाता है, उनमे मिसिसिपी, अलबामा और ओक्लाहोमा के 60 प्रतिशत लोग मानते हैं। वह किसी तरह से अपना खर्च चला पा रहे हैं। अमेरिका के सबसे सस्ते राज्यों की बड़ी आबादी आर्थिक संकट से जूझ रही है। यह स्थिति इस बात का सूचक है कि अमेरिका गहरे आर्थिक संकट में फंस गया है। पिछले एक साल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जिस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, उसके बाद अमेरिका में बदहाली बढ़ती जा रही है। इसका असर सामाजिक स्तर पर बड़े पैमाने पर दिखने लगा है। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। इससे उनमें गुस्सा, नशा और सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका में युवाओं की बहुत बड़ी संख्या अब अपराध की ओर भी जाती हुई दिख रही है। यह वही अमेरिका है, जहां सड़कों पर समृद्धि दिखती है। पूंजीवादियों के ऐशो आराम और अय्याशी को देखकर लगता है, अमेरिका बहुत धनवान है। अमेरिका में रहने वाले लोग बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन अमेरिका की स्थिति ठीक इसके विपरीत है। नागरिकों के मन में असुरक्षा और भय पनप रहा है। अमेरिका एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, जहां उसकी चमकदार छवि और ज़मीनी हकीकत के बीच की खाई गहरी होती जा रही है। अमेरिका में 74 प्रतिशत आबादी के सामने रोज़ी-रोटी का संकट होना अमेरिका के लिए गंभीर चेतावनी है। अमेरिका खुद को दुनिया का नेतृत्वकर्ता मानता है, लेकिन अमेरिका लगातार कर्ज के संकट में फंसता चला जा रहा है। सारी दुनिया में दादागिरी करने के चक्कर में लगातार अपने ही बनाए गए मकड जाल में फंसता जा रहा है। जिसके कारण अब अमेरिका को हर तरफ से चुनौती मिल रही है। यह अमेरिका के उस आर्थिक मॉडल की कहानी है। जो अपने फायदे के लिए किसी भी स्तर तक जाकर अपनी दादागिरी कायम रखना चाहता है। लेकिन अब यही दादागिरी अमेरिका के अस्तित्व के लिए संकट बन गया है। गलत नीतियों के कारण जिस तरह से सोवियत रूस का विघटन हुआ था लगभग वही स्थिति अब अमेरिका की होती हुई दिख रही है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से गरीबों और मध्यम वर्ग को उनके हाल पर छोड़ दिया है। जिस तरह से अमेरिका में अपराध बढ़ रहे हैं। अमेरिका की सरकार पर बढ़ता कर्ज अब अमेरिका के ऊपर भारी पड़ने लगा है। रही सही कसर डॉलर का जो वैश्विक अस्तित्व था अब उसे चुनौती मिल रही है। जिसके कारण आने वाले समय में अमेरिका विघटन की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी पूंजीवादी व्यवस्था को वैश्विक चुनौती मिलना शुरू हो गई है। विश्व में अमेरिका अलग-थलग पड़ता चला जा रहा है। अमेरिका में जिस तरह की स्थितियां बन गई हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ट्रेड डील के बाद विदेशी निवेशकों का भरोसा, भारतीय शेयर बाजार में बढ़ा

मुंबई । अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील को लेकर जो समझौता हुआ है। इसका असर भारत के शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है।विदेशी निवेशकों ने भारत के शेयर बाजार में निवेश करना शुरू कर दिया है। इससे बाजार में तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। ट्रेड डील के बाद विदेशी निवेशकों ने लगभग 15000 करोड रुपए के भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदे हैं। जिसके कारण बाजार में एक बार फिर रौनक आ गई है।विदेशी निवेश आने के कारण डॉलर के मुकाबले रुपए में सुधार हुआ है।विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में छोटी और मझोली कंपनियों के साथ-साथ लार्ज कैप में भी निवेश कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो अंतरिम व्यापार समझौता हुआ है। जिस तरह से आयात शुल्क कम करने की बात सामने आ रही है। भारत से सी-फूड, जेम्स ज्वेलरी, टेक्सटाइल, केमिकल्स, दवाएं और डिफेंस कंपनियों के शेयर में तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि ट्रेड डील के बाद भारत के आयात और निर्यात कारोबार मैं वृद्धि होगी। इसका असर भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है। जिस तरह से दुनिया के देशों में आर्थिक अस्थिरता देखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति में शेयर बाजार में सोच समझकर निवेश करने की जरूरत है। भारत के शेयर बाजार में एक ही समय पर तेजड़िये और मंदडिये सक्रिय हो जाते हैं। उसको देखते हुए शेयर बाजार में स्थिरता बनी रहेगी,यह कहना मुश्किल है।

क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन गुजरात में लगाएगी नया कृषि-रसायन संयंत्र

- कंपनी ने गुजरात में 31 एकड़ भूमि खरीदी, कृषि-रसायन संयंत्र में करेगी 100 करोड़ का निवेश

नई दिल्ली । कृषि-रसायन क्षेत्र की कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन ने गुजरात के झगड़िया में 31.06 एकड़ भूमि खरीदी है। कंपनी अगले तीन वर्षों में इस स्थान पर स्वचालित विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये निवेश करेगी। संयंत्र की प्रारंभिक उत्पादन क्षमता सालाना 50,000 टन होगी। बढ़ती मांग को देखते हुए इसे 1,20,000 टन तक बढ़ाया जा सकेगा। संयंत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। संयंत्र में खरपतवारनाशी, फफूंदनाशी और कीटनाशी तैयार किए जाएंगे। प्रमुख उत्पादों में टॉपर, टिल्ट, प्रोक्लेम, मिसाइल और एसीएम-9 शामिल हैं। कंपनी का लक्ष्य घरेलू बाजार के साथ एशिया और अफ्रीका में निर्यात बढ़ाना है। गुजरात को चयनित करने के पीछे कारण हैं किफायती लागत, नियामकीय स्थिरता और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला। झगड़िया संयंत्र को दहेज, हजीरा और जेएनपीटी बंदरगाहों तक आसान पहुंच भी मिलेगी। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन के एक अे धिकारी ने कहा कि यह संयंत्र कंपनी की वैश्विक प्रतिबद्धता और उत्पादन क्षमता को और मजबूत करेगा।

हैप्पिएस्ट माइंड्स मुनाफा 19.6 प्रतिशत घटकर 40.3 करोड़ हुआ

नई दिल्ली । सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी हैप्पिएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज का अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 19.56 प्रतिशत घटकर 40.3 करोड़ रुपये रह गया। पिछली वित्त वर्ष (2024-25) की समान तिमाही में यह 50.1 करोड़ रुपये था। कंपनी के अनुसार यह गिरावट मुख्य रूप से नए श्रम संहिता के लागू होने से जुड़े एकमुश्त प्रभाव (22.03 करोड़ रुपये) के कारण आई। समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 10.69 प्रतिशत बढ़कर 587.56 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछली तिमाही में यह 530.81 करोड़ रुपये थी। तिमाही आधार पर आय में 2.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मजबूत नकदी प्रवाह और एआई फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ दीर्घकालिक मूल्य सृजन पर ध्यान जारी है। कंपनी एआई और जेन एआई में निवेश बढ़ाएगी और वित्त वर्ष 2026-27 तक 1000 से अधिक लोगों का समर्पित दल बनाने की योजना रखती है।

आरबीआई ने एमएसई के लिए 20 लाख तक का कोलैटरल-फ्री लोन देने की घोषणा की

मुंबई ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत अब एमएसई 20 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे (कोलैटरल-फ्री) ले सकते हैं। यह संशोधन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को लोन देने संबंधी पुराने नियमों में बदलाव है। आरबीआई ने यह भी बताया कि ये नए निर्देश 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। आरबीआई का उद्देश्य है कि सीमित संसाधनों वाले छोटे उद्यमों तक वित्तीय सहायता आसानी से पहुंचे। इससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकेंगे और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा, यह कदम एमएसई क्षेत्र में लोन वितरण प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए भी उठाया गया है। एमएसएमई उद्योगों को मदद देने के लिए सरकार ने भी नए कदम उठाए हैं। डाक चैनल के माध्यम से होने वाले निर्यात को अब आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल जैसे लाभों से जोड़ा गया है। इससे छोटे उद्योग जो डाक सेवा के जरिए विदेशों में सामान भेजते हैं, उन्हें शुल्क और करों में छूट मिलेगी। यह नियम 15 जनवरी 2025 से लागू हैं। छोटे उद्योगों को मिलेंगे फायदे- 20 लाख तक का कोलैटरल-फ्री लोन आसानी से मिलेगा, बैंकिंग प्रक्रिया सरल और तेज होगी, डाक चैनल से निर्यात करने वाले उद्योगों को वित्तीय और कर लाभ प्राप्त होंगे एवं एमएसई क्षेत्र का विकास और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। आरबीआई और सरकार के इन कदमों से छोटे और लघु उद्यमों को वित्तीय और बाजार में स्थिरता मिलने की संभावना है, जिससे देश के एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई । अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मंगलवार को भारतीय रुपया 20 पैसे की गिरावट के साथ ही 90.48 रुपये पर बंद हुआ। आज सुबह रुपया शुरुआती कारोबार में 11 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.77 पर पहुंच गया। भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति के बाद से मुद्रा बाजार में उत्साह की बजाय सतर्कता का माहौल बना हुआ है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.63 पर खुला। फिर और टूटकर 90.77 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से 11 पैसे की गिरावट दिखाता है। रुपया सोमवार को उतार-चढ़ाव भरा कारोबार करते हुए अंत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.66 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.02 फीसदी की गिरावट के साथ 97.79 पर रहा।

बांग्लादेश-अमेरिका व्यापार समझौते से आरएमजी क्षेत्र को बड़ी राहत

ढाका ।

बांग्लादेश और अमेरिका ने व्यापार समझौते पर सहमति जताई है, जिसके तहत बांग्लादेश से आने वाले कुछ वस्त्र और परिधान उत्पादों पर अमेरिकी शुल्क को घटाकर 19 फीसदी कर दिया गया है। खासकर अमेरिका में उत्पादित कपास और मानव निर्मित फाइबर से बने रेडीमेड गारमेंट्स (आरएमजी) को शून्य शुल्क पर अमेरिकी बाजार में प्रवेश मिलेगा। यह समझौता नौ महीने की बातचीत के बाद हुआ है। समझौते में अमेरिका से गेहूं, सोयाबीन और एलएनजी आयात, ई-कॉमर्स पर शुल्क न लगाना, अमेरिकी बौद्धिक संपदा अधिकार मानकों का पालन और डब्ल्यूटीओ सुधारों में सहयोग जैसे प्रावधान शामिल हैं। अमेरिका में वाणिज्य सलाहकार शेख बशीर उद्दीन और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। आरएमजी क्षेत्र बांग्लादेश की कुल निर्यात आय में 80 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी रखता है। यह क्षेत्र लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार देता है, जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं, और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका योगदान करीब 10 फीसदी है। व्यापार विश्लेषकों का मानना है कि यह समझौता निर्यातकों के लिए बड़ी राहत है। समझौता ऐसे समय हुआ है जब बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। अमेरिकी शुल्क कटौती पर हाल ही में अमेरिका-भारत व्यापार समझौते का भी प्रभाव पड़ा हो सकता है। बांग्लादेश के मुख्य प्रतिस्पर्धी वियतनाम पर 20 फीसदी शुल्क, जबकि पाकिस्तान, कंबोडिया और इंडोनेशिया पर 19 फीसदी शुल्क लगाया गया है। बांग्लादेश ने अमेरिकी बोइंग से 25 विमान खरीदने की सहमति दी है, जिसकी अनुमानित लागत 30,000-35,000 करोड़ टका है। यह कदम अमेरिकी शुल्क में रियायत पाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 208 , निफ्टी 67 अंक ऊपर आया

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये तेजी दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीदारी हावी रहने से आई है। आज वाहन और धातु शेयरों में जमकर खरीदारी हुई जिससे बाजार को बल मिला। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स अंत में 208.17 अंक बढ़कर 84,273.92 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 67.85 अंक उछलकर 25,935.15 पर बंद हुआ। आज निफ्टी ऑटो , निफ्टी मेटल , निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी इंडिया डिफेंस , निफ्टी पीएसई और निफ्टी कमोडिटीज के शेयरों में तेजी रही जबकि फ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थकेयर और निफ्टी पीएसयू बैंक के शेयरों में गिरावट रही।

आज लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी तेजी रही। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 294.75 अंक बढ़कर 60,735.90 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 65.30 अंक उछलकर 17,451.20 अंक पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, एमएंडएम, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, एलएंडटी, टीसीएस, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, टाइटन, सन फार्मा और बजाज फिनसर्व के शेयरों को लाभ हुआ जबकि एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी, एसबीआई, इंडिगो और बीईएल के शेयर गिरे।

इससे पहले आज सुबह बाजार की मजबूती के साथ शुरुआत हुई। सुबह बीएसई सेंसेक्स अपने पिछले बंद स्तर से करीब 144 अंकों की तेजी के साथ 84,210 के स्तर पर खुला और शुरुआती कारोबार में 84,270 के आसपास पहुंच गया। वहीं निफ्टी 50 भी करीब 57 अंकों की बढ़त के साथ 25,922.65 के स्तर पर कारोबार शुरू किया। सुबह शुरुआत के बाद सेंसेक्स 200 से ज्यादा अंकों की मजबूती के साथ 84,270 के ऊपर ट्रेड करता दिखा। निफ्टी भी 56 अंकों की तेजी के साथ 25,924 के आसपास बना रहा। आजएशियाई बाजारों में जापान का निक्केई, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजार हरे निशान में कारोबार करते नजर आए।

मोटर वाहन बिक्री में जोरदार उछाल, ग्रामीण बाजार में मांग बढ़ी

- जनवरी में यात्री वाहन बिक्री 5,13,475 इकाई रही, एक साल पहले 4,78,915 से 7 प्रतिशत अधिक

नई दिल्ली ।

देश में जनवरी 2026 में मोटर वाहनों की खुदरा बिक्री में सालाना आधार पर लगभग 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वाहन डीलर निकाय फाडा के अनुसार कुल बिक्री 27,22,558 इकाई रही, जो जनवरी 2025 की 23,14,940 इकाई की तुलना में 17.61 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर नकदी प्रवाह, जीएसटी में बदलाव के बाद नीति स्थिरता और मालवाहन मांग में स्पष्टता से जुड़ी है। जनवरी में यात्री वाहन बिक्री 5,13,475 इकाई रही, जो एक साल पहले की 4,78,915 इकाई से 7 प्रतिशत अधिक है। फाडा के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सालाना आधार पर बिक्री 14.43 प्रतिशत बढ़ी, जबकि शहरी क्षेत्र में सिर्फ 2.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में एसयूवी/कॉम्पैक्ट एसयूवी की लोकप्रियता, छोटी कारों की वापसी और उत्पाद उपलब्धता का योगदान रहा। दो-पहिया वाहनों की खुदरा बिक्री में सालाना 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 18,52,870 इकाई तक पहुंच गई। ट्रैक्टर की बिक्री भी 23 प्रतिशत बढ़कर 1,14,759 इकाई हो गई। विग्नेश्वर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में त्योहारों, शादी के मौसम और बेहतर वहनीयता से मांग में इजाफा हुआ है। तीन-पहिया वाहनों की बिक्री में 19 प्रतिशत और वाणिज्यिक वाहनों में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। इन आंकड़ों से मालवाहन और छोटे व्यवसायों में मांग की स्थिरता का संकेत मिलता है। फाडा के सर्वेक्षण के अनुसार, 79.7 प्रतिशत डीलर आगामी तीन महीनों में बिक्री वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि केवल 1.88 प्रतिशत ने गिरावट की आशंका जताई। जीएसटी में बदलाव, कृषि और बुनियादी ढांचा पर जोर देने वाला बजट, और ब्याज दरों की स्थिरता से वाहन खरीद में उत्साह बढ़ा है।

एक्मे सोलर को मध्य प्रदेश में 220 मेगावाट की सौर परियोजना मिली

नई दिल्ली । एक्मे सोलर होल्डिंग्स को मध्य प्रदेश के मुरैना सोलर पार्क में 220 मेगावाट की सौर परियोजना मिली है। इस परियोजना में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) भी शामिल होगी। यह परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा जारी 440 मेगावाट की निविदा का हिस्सा है। परियोजना के लिए निविदा दर-आधारित प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के तहत जारी की गई थी। नीलामी सितंबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स तरीके से आयोजित की गई। परियोजना का अधिकतम वार्षिक क्षमता उपयोग कारक 35 प्रतिशत है। सुबह और शाम दो-दो घंटे, कुल चार घंटे की उच्चतम मांग आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। इस दौरान बिजली की सालाना 95 प्रतिशत उपलब्धता अनिवार्य है। परियोजना 25 साल की विद्युत खरीद संधि (पीपीए) के तहत संचालित होगी। इसमें सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण तकनीक का संयोजन होगा। विद्युत खरीद संधि मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के साथ होगी।

इक्विटी म्यूचुअल फंड में गिरावट, गोल्ड और ऋण फंड में निवेश बढ़ा

- जनवरी में निवेश 24,028 करोड़, जो दिसंबर के 28,054 करोड़ की तुलना में 14 प्रतिशत कम

नई दिल्ली ।

जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 24,028 करोड़ रुपये रह गया, जो दिसंबर के 28,054 करोड़ रुपये की तुलना में 14 प्रतिशत कम है। यह लगातार दूसरा महीना है जब इक्विटी निवेश में गिरावट दर्ज की गई। कमजोर बाजार हालात और वैश्विक भू-राजनीतिक चिंताओं के बीच निवेशक सतर्क बने हुए हैं। अक्टूबर में इक्विटी निवेश 24,690 करोड़ रुपये था, जबकि नवंबर में यह 29,911 करोड़ रुपये था। इक्विटी निवेश में सुस्ती के बावजूद म्यूचुअल फंड उद्योग की कुल प्रबंध अधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) बढ़कर 81.01 लाख करोड़ रुपये हो गईं, जो दिसंबर में 80.23 लाख करोड़ रुपये थी। जनवरी में उद्योग में कुल शुद्ध निवेश 1.56 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि दिसंबर में 66,591 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी। फ्लेक्सी-कैप फंड में सबसे अधिक 7,672 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ। इसके बाद मिड-कैप फंड में 3,185 करोड़ रुपये और लार्ज व मिड-कैप फंड में 3,182 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। लार्ज-कैप और स्मॉल-कैप फंड में क्रमशः 2,005 करोड़ और 2,942 करोड़ रुपये का निवेश दर्ज किया गया। कर बचत योजनाओं में 593.69 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी हुई, जो मुनाफावसूली और कर समायोजन को दर्शाती है।

गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में मांग तेजी से बढ़ी और निवेश दिसंबर के 11,647 करोड़ रुपये से बढ़कर जनवरी में 24,040 करोड़ रुपये हो गया। ऋण म्यूचुअल फंड में भी सुधार दिखा और जनवरी में 74,827 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश दर्ज हुआ, जबकि दिसंबर में इसमें 1.32 लाख करोड़ रुपये की निकासी हुई थी।

भारत को फार्मा नवाचार हब बनाने नियामकीय सुधार जरूरी: उद्योग दिग्गज

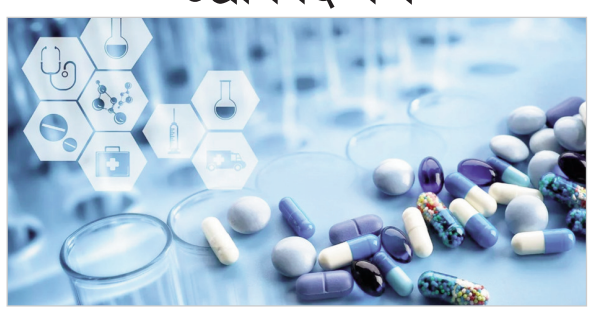

अनुमोदन प्रक्रिया को आसान और तेज करना जरूरी

नई दिल्ली ।

देश के फार्मास्युटिकल उद्योग के प्रमुखों ने कहा है कि भारत को नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए तेज, सरल और भरोसेमंद नियामक तंत्र की आवश्यकता है। उद्योग ने आगाह किया कि मंजूरी में देरी, क्लीनिकल परीक्षणों का कमजोर बुनियादी ढांचा और घरेलू नवाचार की कम स्वीकार्यता भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ रही है, जबकि चीन जैसे देश तेजी से मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। सन फार्मा के एक प्रमुख अे धिकारी ने बताया कि भारत में मंजूरी मिलने से पहले अक्सर चरण-1 के परीक्षण बेल्जियम या ऑस्ट्रेलिया में पूरे हो जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अगर देश नवाचार का हब बनना चाहता है तो अनुमोदन प्रक्रिया को आसान और तेज करना जरूरी है। उद्योग के दिग्गजों ने हाल ही में लागू की गई सरकारी योजनाओं का स्वागत किया। इनमें पीआरआईपी योजना और 1,000 क्लीनिकल परीक्षण केंद्रों को प्रमाणित करने की पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि यह संकेत सकारात्मक हैं, लेकिन असली चुनौती इन पर प्रभावी अमल करना है। उद्योग के दिग्गजों ने मिलकर जोर दिया कि भारत को केवल जेनेरिक दवाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मूल्यवान नवाचार दवाओं के निर्माण की दिशा में तेजी से बढ़ना चाहिए।

उद्योग के दिग्गजों का मानना है कि भारत फार्मा नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व हासिल कर सकता है, यदि नियामकीय प्रक्रियाओं में सुधार, क्लीनिकल परीक्षणों का मजबूत ढांचा और नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाए।

छमाही में कंपनियों का कैपेक्स 6 साल के उच्च स्तर पर

वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में कंपनियों का पूंजीगत खर्च 13.1 फीसदी बढ़ा

नई दिल्ली ।

भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र में निवेश गतिविधियां तेज़ होती दिख रही हैं। चालू वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में सूचीबद्ध कंपनियों के पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बैंक, वित्त और बीमा (बीएफएसआई) तथा तेल एवं गैस क्षेत्र को छोड़ दें तो अन्य क्षेत्रों की कंपनियों की कुल स्थिर संपत्तियां इस अवधि में 13.1 फीसदी बढ़ीं, जो पिछले छह वर्षों में सबसे तेज़ वृद्धि है। 702 कंपनियों की कुल स्थिर संपत्तियां सितंबर 2025 के अंत तक बढ़कर 37.78 लाख करोड़ रुपये हो गईं। इससे पहले यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2025 की समान अवधि में 33.41 लाख करोड़ रुपये और मार्च 2025 के अंत में 36.33 लाख करोड़ रुपये था। इसके मुकाबले वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में कैपेक्स वृद्धि 7.9 फीसदी और दूसरी छमाही में 6.9 फीसदी रही थी। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी का मुख्य श्रेय सीमेंट, बिजली, निर्माण एवं बुनियादी ढांचा, खनन, धातु और वाहन क्षेत्रों को जाता है। इस दौरान ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने सबसे बड़ा योगदान दिया। इसके बाद अदाणी एंटरप्राइजेज, एनटीपीसी, टाटा स्टील और पावर ग्रिड का स्थान रहा। कुल कैपेक्स में इन पांच कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 30 फीसदी रही। ग्रासिम की स्थिर संपत्तियां सालाना आधार पर 30 फीसदी बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपये हो गईं, जिसका बड़ा कारण उसकी सीमेंट इकाई अल्ट्राटेक सीमेंट का विस्तार है। अल्ट्राटेक की स्थिर संपत्तियां पहली छमाही में 41.2 फीसदी बढ़ीं। इसके अलावा कई कंपनियों में अधिग्रहण के चलते भी स्थिर संपत्तियों में तेज़ बढ़ोतरी दर्ज की गई। यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल और ओएनजीसी को शामिल किया जाए, तो इस अवधि में कॉरपोरेट कैपेक्स वृद्धि 20 फीसदी से अधिक रही।

पीएमआईएस में होगा बदलाव, इंटर्नशिप अवधि और आयु सीमा में कमी पर विचार

पायलट चरण में 1 लाख प्रशिक्षुओं की भागीदारी

नई दिल्ली । कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) की प्रायोगिक परियोजना में सुधारों का प्रस्ताव व्यय वित्त समिति को सौंपा है। मंत्रालय ने कहा कि योजना को उम्मीदवारों के लिए और अधिक सुलभ और आकर्षक बनाने के लिए इंटर्नशिप की अवधि और आयु सीमा में कमी पर विचार किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि योजना को पूरी तरह लागू करने से पहले इन बदलावों के साथ उसका परीक्षण किया जाएगा।

पायलट चरण में लगभग 1 लाख प्रशिक्षुओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 840 करोड़ रुपये के बजट के साथ योजना की प्रायोगिक परियोजना को मंजूरी दी गई थी। संसद में दिए गए जवाब के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 31 दिसंबर तक पायलट परियोजना में 64.91 करोड़ रुपये खर्च किए गए। अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए योजना के लिए 4,800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसी वर्ष मंत्रालय ने संशोधित अनुमान के तहत 10,831 करोड़ रुपये में से 541 करोड़ रुपये खर्च किए। पहले चरण में 1.81 लाख उम्मीदवारों से 6.21 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,417 प्रशिक्षुओं ने इंटर्नशिप पूरी की। प्रायोगिक परियोजना के दोनों चरणों में कुल 7,094 उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप बीच में छोड़ दी। दूसरे चरण में 4.55 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

टी20 विश्वकप : डि लीडे के हरफनमौला प्रदर्शन से नीदरलैंड ने नामीबिया को सात विकेट से हराया

नई दिल्ली (एजेंसी)। मंगलवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के 10वें मैच में, बास डी लीडे के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत नीदरलैंड्स ने नामीबिया पर सात विकेट से जीत दर्ज की। पाकिस्तान से पहले मैच में मिली करीबी हार के बाद, नीदरलैंड्स ने नामीबिया पर शानदार जीत के साथ टी20 विश्व कप में अपनी उम्मीदों पर फिर से सवार हो गया। इस जीत के सूत्रधार बास डी लीडे रहे, जो नीदरलैंड्स के लिए बल्ले और गेंद दोनों से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी साबित हुए। उन्होंने गेंद से नामीबिया को ध्वस्त कर दिया (3 ओवर में 2/20) और फिर पांच चौकों और चार छक्कों सहित 48 गेंदों पर शानदार नाबाद 72 रनों की पारी खेलकर नीदरलैंड्स को लक्ष्य के करीब पहुंचाया।

पहले फील्डिंग करने का विकल्प चुनते हुए, डच गेंदबाजों को तुरंत सफलता मिली क्योंकि आर्यन दत्त (3 ओवर में 1/13) ने नामीबिया के सलामी बल्लेबाज लौरेन स्टीनकैंप को जल्दी आउट कर दिया। पावरप्ले में नामीबिया को लय हासिल करने में काफी संघर्ष करना पड़ा और 6 ओवर के बाद उसका स्कोर मात्र 40/1 रहा। जान निकोल लॉफ्टी-ईटन (38 गेंदों में 42 रन) और जान फ्रायलिंक (26 गेंदों में 30 रन) ने पारी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन नीदरलैंड की अनुशासित गेंदबाजी ने रन रेट को नियंत्रण में रखा।

मध्य ओवर बास डी लीड और लोगान वैन बीक (3 ओवर में 2/13) के नाम रहे, जिन्होंने मिलकर चार विकेट लिए। डी लीड ने खतरनाक गेरहार्ड इरास्मस और जेजे स्मिट को आउट किया। नामीबिया अंततः 20 ओवर में 156/8 के प्रतिस्पर्धी लेकिन कम स्कोर पर समाप्त हुआ। मैक्स ओ'डॉउड के बर्नार्ड स्कोल्ट्ज़ के हाथों जल्दी आउट होने के बावजूद, डच टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत की। माइकल लेविट (15 गेंदों में 28 रन) ने जल्दी बल्लेबाजी करते हुए आउट हो गए, जिससे नीदरलैंड्स का स्कोर छह ओवरों में 50/2 हो गया।

इसके बाद, बास डी लीड का जलवा रहा। कॉलिन एकरमैन (28 गेंदों में 32 रन) के साथ साझेदारी करते हुए, डी लीड ने संयम से पारी को संभाला और फिर तेजी से रन बनाने लगे। उन्होंने मात्र 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि एकरमैन लॉफ्टी-ईटन के हाथों आउट हो गए, लेकिन परिणाम को लेकर कोई संदेह नहीं था। डी लीड (48 गेंदों में 72*) और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स (9 गेंदों में 18*) ने 12 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया और एक शानदार चौके के साथ मैच समाप्त किया।

सिफर्ट और एलन की ताबड़तोड़ पारी, न्यूजीलैंड ने यूएई को 10 विकेट से रौंदा

चेन्नई। टिम सिफर्ट (नाबाद 89) और फिन एलन (नाबाद 84) की आक्रामक पारियों और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 92 गेंद में 175 रन की रिकॉर्ड साझेदारी ने न्यूजीलैंड ने आईसीसी टी20 विश्व कप मैच में मंगलवार को यहां 28 गेंद शेष रहते संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 10 विकेट से शिकस्त देकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। यूएई को छह विकेट पर 173 रन पर रोकने के बाद न्यूजीलैंड ने महज 15.2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 175 रन बनाकर एकतरफा जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड की यह लगातार दूसरी जीत है। टीम ने इससे पहले अफगानिस्तान को हराया था। 'प्लेयर ऑफ द मैच' सिफर्ट ने 42 गेंद की नाबाद पारी में 12 चौके और तीन छक्के लगाये। एलन ने 50 गेंद की नाबाद पारी में पांच छक्के और इतने ही चौके लगाये, इसके साथ उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 छक्के पूरे किए। इस जोड़ी ने पारी की शुरुआत से ही आक्रामक रूख अपनाते हुए यूएई के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। दोनों की 175 रन की साझेदारी टी20 विश्व कप में किसी भी विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है। कप्तान मोहम्मद वसीम (नाबाद 66) और अलीशाह शराफू (55) की अर्धशतकीय पारियों और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने छह विकेट पर 173 रन बनाए।

>> छः हज़ार प्रतियोगियों ने लिया हिस्सा

वनबंधु परिषद द्वारा हाफ मैराथन एकल रन 3.0 का हुआ भव्य आयोजन

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत,वनवासी समाज उत्थान को समर्पित फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल्स सोसायटी (वनबंधु परिषद) द्वारा रविवार को हाफ मैराथन एकल रन 3.0 का आयोजन वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से सुबह छः बजे किया गया।

सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। इस अवसर पर वीएनएसजीयू के कुलपति डॉ. किशोर सिंह चावड़ा तथा वनबंधु परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष त्रिभुवन काबरा भी उपस्थित रहें। एकल रन में 6 हजार से अधिक रनर्स एवं पेसर्स ने सहभागिता की, जिनमें से लगभग 500 प्रतिभागी सूरत के बाहर से आए। 'रन टू एजुकेट' के ध्येय वाक्य को साकार करते हुए इस दौड़ ने वनवासी समाज की शिक्षा के प्रति जन-जागरूकता का सशक्त संदेश दिया। 'छोटे कदम - बड़े इरादे' के मूल मंत्र के साथ आयोजित एकल रन 3.0 न केवल एक खेल आयोजन रहा, बल्कि सामाजिक सरोकार, शिक्षा और एकता का प्रेरणादायी उत्सव बनकर उभरा।

एकल रन में प्रतिभागियों ने पार्टी सूट, साड़ी आदि पहनकर भारत की एकता का परिचय दिया। अलग-अलग श्रेणी में विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सभी रनर के लिए पानी, मेडिकल, ड्रेस किट, मेडल, अल्पाहार आदि की व्यवस्था की गई थी।

आयोजन में कार्यक्रम के स्पॉन्सर्स विशाल बुधिया, राजेश गुप्ता, अरविंद कोठारी, महेश जरीवाला के अलावा संस्था के संरक्षक प्रमोद चौधरी, वेस्ट जोन चेयरमैन श्याम गर्ग, एकल रन के चेयरमैन श्रीनारायण पेड़ीवाल, रेस डायरेक्टर ललित पेड़ीवाल, इवेंट कोऑर्डिनेटर युवा टीम के गौतम प्रजापति, गोपेश अग्रवाल, अनुराग जैन, जय स्वर्णकार सहित अनेकों पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहें।

पीएम मोदी से मिलने के बाद रवींद्र जडेजा की पहली प्रतिक्रिया आई सामने

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, अपनी पत्नी रीवाबा जडेजा और गुजरात की ट्राइबल डेवलपमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी और एडल्ट एजुकेशन मिनिस्टर के साथ मंगलवार को नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। जडेजा ने अपनी मीटिंग की तस्वीरें पोस्ट करते हुए X पर लिखा, 'माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी सर से मिलना और बातचीत करना बहुत गर्व और सम्मान की बात है। उनके विचारों की स्पष्टता, उत्साह और बेहतरीन काम के लिए कमिटमेंट बहुत प्रेरणा देने वाला है। ऐसी लीडरशिप से सीखना गर्व की बात है।'

यह मीटिंग ऐसे समय में हुई जब जडेजा भारतीय क्रिकेट के सीनियर खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्हें सोमवार को घोषित BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की एलीट A कैटेगरी में रखा गया है। वह टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह के साथ यह दर्जा पाने वाले केवल तीन खिलाड़ियों में से एक थे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली के 20 ओवर के खेल से रिटायरमेंट के बाद जडेजा ने टी20 इंटरनेशनल मैचों से दूरी बना ली है और सबसे छोटे फॉर्मेट में अपने करियर को अलविदा कह दिया है। इस वजह से वह भारत और श्रीलंका की को-होस्टिंग में चल रहे ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की टीम का हिस्सा नहीं हैं।

टी20 वर्ल्ड कप: पाकिस्तान सरकार का यू-टर्न!

15 फरवरी को खेला जाएगा भारत-पाक के बीच हाई वोल्टेज मैच

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान सरकार ने पुरुष क्रिकेट टीम को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अपना तय मैच खेलने की इजाजत दे दी है। यह मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है।

उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने आईसीसी से अपने मुकाबले भारत के बजाय किसी अन्य वेन्यू पर शिफ्ट करने की अपील की थी, लेकिन आईसीसी ने बीसीबी की अपील को ठुकरा दिया, जिसके बाद बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल किया गया।

इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने पहले टीम से कहा था कि भारत के खिलाफ मैच न खेले, ताकि बांग्लादेश को समर्थन दिखाया जा सके, लेकिन आईसीसी की ओर से भारत के मैच का बहिष्कार करने की पाकिस्तान की धमकी पर कड़ा रुख अपनाने और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) और श्रीलंका सरकार की ओर से पाकिस्तान से अपने फैसले पर फिर से विचार करने के अनुरोध के बाद, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पुरुष टीम को मैच खेलने

की इजाजत दे दी है।

पाकिस्तान सरकार ने कहा कि उसने बांग्लादेश और श्रीलंका के अनुरोधों के कारण अपनी टीम को 15 फरवरी का मैच खेलने की अनुमति दी है।

पाकिस्तान सरकार ने कहा, 'पाकिस्तान सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा पीसीबी को भेजे गए औपचारिक अनुरोधों के साथ-साथ श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य सदस्य देशों के समर्थन संदेशों की समीक्षा की है। इन संदेशों में हाल की चुनौतियों का एक समाधान खोजने में पाकिस्तान के नेतृत्व की मांग की गई थी। सरकार ने बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम के बयान पर भी गौर किया। हमारे भाईचारे वाले देश की ओर से व्यक्त की गई गहरी कृतज्ञता को बहुत गर्मजोशी से स्वीकार किया गया। पाकिस्तान इस बात की पुष्टि करता है कि वह बांग्लादेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।

बयान में कहा गया है, 'रविवार शाम, प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से टेलीफोन पर बात की। अपनी गर्मजोशी भरी और मैत्रीपूर्ण बातचीत के दौरान, उन्होंने याद किया कि पाकिस्तान और श्रीलंका हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, खासकर चुनौतीपूर्ण समय में। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से मौजूदा गतिरोध को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया।'

सोमवार रात को पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, 'बहुपक्षीय चर्चा के नतीजों और मित्र देशों के अनुरोध को देखते हुए, पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में अपने तय मैच के लिए 15 फरवरी 2026 को मैदान में उतरने का निर्देश देती है।'

डी कॉक ने धोनी के एक विश्व रिकार्ड की बराबरी की

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक कनाडा के खिलाफ हुए टी20 विश्वकप क्रिकेट मैच में बल्लेबाजी में तो असफल रहे पर उन्होंने इस मैच में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी के एक विश्व रिकार्ड की जरुर बराबरी कर ली। डी कॉक ने कनाडा के खिलाफ हुए मुकाबले में दो कैच पकड़े। इसी के साथ उन्होंने धोनी के टी20 विश्वकप में विकेटकीपर के तौर पर सबसे अधिक 32 खिलाड़ियों को आउट करने के रिकार्ड की बराबरी कर ली। अब डी कॉक के पास अगले मैच में धोनी का रिकार्ड तोड़ने का अच्छा अवसर है।

टी20 विश्वकप में विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज्यादा आउट करने वाले खिलाड़ियों में तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल हैं। कामरान ने विकेट के पीछे 30 शिकार किये हैं। वहीं वेस्टइंडीज के दिनेश रामदीन चौथे 27 और श्रीलंके के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा 26 शिकार के साथ ही पांचवें पायदान पर हैं। मैच की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने कप्तान एडन मार्करम के 59 रनों की पारी से निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए। वहीं कनाडा की ओर से अंश पटेल ने 31 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके बाद जीत के लिए मिले 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कनाडा की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 156 रन पर ही आउट हो गयी। केवल नवनीत धालीवाल ही 64 बना पाये। वहीं बाकि बल्लेबाज असफल रहे।

टी20 विश्वकप : वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के इरादे से उतरेगी इंग्लैंड

मुंबई (एजेंसी)। इंग्लैंड की टीम बुधवार को ग्रुप सी के अपने दूसरे मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ बड़ी जीत के इरादे से उतरेगी। इंग्लैंड को पहले मैच में नेपाल जैसी कमजोर टीम के खिलाफ कड़ा संघर्ष करने के बाद भी केवल 4 रनों से ही जीत मिली थी। ऐसे में उसका लक्ष्य वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना रहेगा। उसके लिए ये इतना भी कठिन नहीं है क्योंकि वेस्टइंडीज टीम भी काफी कमजोर है और उसके खिलाड़ी लय में नहीं हैं।

टी20 में हालांकि किसी भी टीम को कम नहीं आंका जा सकता है। हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम के पास सैम करन जैसे अच्छा गेंदबाज है। नेपाल के खिलाफ सैम ने अंतिम ओवर में केवल 5 रन ही देकर अपनी टीम को जीत दिलायी थी। उन्होंने अंतिम ओवर में लाइन और लेंथ से नेपाल के

बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई अवसर नहीं दिया। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने हालांकि मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था पर उसके स्पिनर आदिल राशिद और तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर प्रभावित नहीं कर पाये। इससे नेपाल के बल्लेबाज मैच को अंत तक ले जाने में सफल रहे। मैच में कप्तान हैरी और युवा जैकब बेथेल ने अर्धशतक लगाए। इसके अलावा अन्य बल्लेबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। इंग्लैंड की टीम इस मैच में अपना रन औसत भी बेहतर करना चाहेगी। नेपाल के खिलाफ जीत के बाद भी उसका औसत 0.200 है और वह तीसरे स्थान पर हैं जबकि स्कॉटलैंड दो अंकों और 0.950 के नेट रन औसल के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं वेस्टइंडीज के भी दो अंक हैं और उसका नेट रन औसत 1.750 है। दूसरी ओर वेस्टइंडीज जानता है कि इस मैच में उसे हर हाल में जीतना होगा।

वानखेड़े स्टेडियम में छोटी बाउंड्री से भी इस मैच में रनों को बनाना आसान रहेगा। वेस्टइंडीज ने अपने पहले मैच में शिमरोन हेटमायर के अर्धशतक 64 रनों के अलावा रोमारियो शेफर्ड के पांच विकेटों की सहायता से स्कॉटलैंड को हराया था पर उसे इसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। ऐसे में अगर उसे इस मैच में जीतना है तो सभी खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।

यूएफा महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर हैं मनीषा, एलियांजा लीमा क्लब से खेलेंगी

लीमा। भारतीय महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण मनीषा यूएफा महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर हैं। इसके बाद से ही उन्हें विदेशी लीग से प्रस्ताव मिलने शुरु हुए। अब मनीषा पेरु के क्लब एलियांजा लीमा से खेलती हुई नजर आयेंगी। मिडफील्डर मनीषा ने हाल ही में इस क्लब से करार किया है। मनीषा के अनुसार इससे उन्हें काफी कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। मनीष के अनुसार वह इस टीम की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा, ''मैं इस क्लब में आकर बहुत खुश हूं। मुझे उनका खेलने का अंदाज काफी अच्छा लगता है।मैं अब इस नई चुनौती को लेकर बेहद उत्साहित हूं। वहीं क्लब एलियांजा ने कहा, ''मनीषा के साथ करार से हमें खुशी हुई है। उनके आने से हैं टीम को मजबूत मिलेगी। उन्होंने यूरोपीय फुटबॉल के शीर्ष स्तर पर खेला है जिसका लाभ क्लब को मिलेगा।'' साथ ही कहा, ''कल्याण ने क्लब और राष्ट्रीय टीम दोनों स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। उनके पेशेवर करियर में भारत, साइप्रस और यूनान की लीग में खेलने का अनुभव शामिल है। ''वहीं मनीषा ने कहा कि उसका प्रयास क्लब के लिए बेहतर प्रदर्शन करना रहेगा। उनका घ्यान अपना सौ फीसदी देने पर रहेगा।

सूर्यकुमार ने कप्तान के तौर पर अपने को साबित किया : गंभीर

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह मेरा काम आसान कर देते हैं। गंभीर ने कहा कि टी20 प्रारुप में कप्तान बनाये जाने के बाद से ही सूर्या ने अपनी जिम्मेदारी काफी अच्छे से निभाई है। वह हर प्रकार से सफल रहे है। दबाव के बीच भी उनकी नेतृत्व क्षमता को सभी ने देखा है। एक वीडियो में गंभीर ने कहा कि टीम में सूर्यकुमार जैसे आक्रामक बल्लेबाज से भारतीय टीम को काफी लाभ होता है। टीम के लिए ये खुशी की बात है कि उसे ऐसा कप्तान और बल्लेबाज मिला है जो संयमित रहते हुए सभी का सही उपयोग करता है। इससे कोच के तौर पर मेरा काम भी आसान हो गया है। गंभीर ने कहा, 'सूर्यकुमार ने इस प्रारूप में मेरा काम कर कर दिया है। वह लोगों के लिए एक बेहतरीन कप्तान हैं, यह केवल नहीं कि वह मैदान पर क्या करते हैं, या बल्लेबाज के रूप में कैसे हैं, या उनके शॉट्स इस प्रारूप में किस प्रकार के हैं।' कोच के तौर पर दिमाग में कई बातें चल रही होती हैं पर सूर्यकुमार माहौल को शांत बनाए रखते है, जो हर कोच चाहता है।' सूर्यकुमार ने पहले ही मैच में अमेरिका के खिलाफ पारी को संभालकर टीम को जीत दिलायी। उन्होंने एक छोर से विकेटों के गिरने के बची भी 49 गेंदों में नाबाद 84 रन बनाकर टीम को मैच में बनाये रखा। गंभीर ने कहा, 'मेरे लिए खिलाड़ी सूर्यकुमार को अलग रखा जा सकता है पर कप्तान सूर्यकुमार के तौर पर वह हर परीक्षा खरे उतरे हैं। इससे मुझे भी काफी आराम मिल गया है क्यों मेरा काफी काम वहीं कर देते हैं। वह वास्तव में एक शानदार नेतृत्वकर्ता हैं।' यह सौभाग्य की बात है कि देश का नेतृत्व उनके जैसे खिलाड़ी के हाथ में है, क्योंकि उनका दिल सही जगह पर है और दबाव में वह सही फैसला लेते हैं।' गौरतलब है कि रोहित शर्मा के टी20 से संन्यास के बाद गंभीर ने ही सूर्या को कप्तानी देने की मांग की थी।

कतर ओपन : झेंग की दमदार वापसी, एंड्रीएवा अंतिम-16 में

दोहा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता झेंग किनवेन ने चोट से वापसी करते हुए कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शानदार जीत दर्ज की। झेंग ने सोमवार को खेले गए मुकाबले में 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता सोफिया केनिन को तीन सेटों के संघर्षपूर्ण मैच में

4-6, 6-1, 6-2 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। अब उनका सामना एलिसिया पार्क्स से होगा। सितंबर पिछले साल के बाद पहली बार प्रतिस्पर्धी टेनिस में उतरीं झेंग इस समय विश्व रैंकिंग में 26वें स्थान पर हैं। सीजन के अपने पहले ही मैच में उन्होंने 20 ऐस जमाकर जोरदार संदेश दिया। मैच के बाद झेंग ने कहा, 'चोट के बाद वापसी कभी पूरी तरह दर्द-मुक्त नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी कोहनी सही दिशा में ठीक हो रही है। मैं अच्छी स्थिति में हूं और दो घंटे तक सर्व करते हुए खेल जारी रख सकती हूं।' उधर, पांचवीं वरीयता प्राप्त मिर्रा एंड्रीएवा ने राउंड ऑफ 64 में बाई मिलने के बाद अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। उन्होंने मग्दा लिनेट को 7-6 (7/0), 6-1 से हराकर अंतिम-16 में जगह बनाई। दिन के मुकाबलों में कुछ बड़े उलटफेर भी देखने को मिले। तीसरी वरीयता प्राप्त अमांडा एनिसिमोवा करोलिना प्लिस्कोवा के खिलाफ तीसरे सेट में पिछड़ते हुए मुकाबले से हट गईं। वहीं, पूर्व यूएस ओपन चैंपियन एमा राडुकानू को भी कैमिला ओसोरियो के खिलाफ निर्णायक सेट में रिटायर होना पड़ा। मंगलवार को शीर्ष दो वरीयता प्राप्त इगा स्वियातेक और एलेना रयबाकिना राउंड ऑफ 32 में अपने-अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। चौथी वरीयता कोको गॉफ भी सिंगल्स में अपना पहला मुकाबला खेलेंगी। गॉफ को सोमवार को उभरती स्टार विक्टोरिया म्बोको के साथ डबल्स में हार का सामना करना पड़ा था।

पाकिस्तान के यू-टर्न के बाद सौरव गांगुली का बड़ा बयान, टी20 वर्ल्ड कप में भारत से जीतना मुश्किल

मुम्बई (एजेंसी)। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने 15 फरवरी को कोलंबो में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त की और भारतीय टीम के अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के नाम भी बताए। पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप ए के मैच पर प्रतिक्रिया देते हुए गांगुली ने कहा कि यह विश्व कप का एक बड़ा मुकाबला होगा। मैच 15 फरवरी को है, पाकिस्तान के लिए भारत को हराना आसान नहीं होगा। भारत एक बहुत अच्छी टीम है।

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष की यह टिप्पणी पाकिस्तान सरकार द्वारा सोमवार को दिए गए निर्देश के बाद आई है, जिसमें उन्होंने अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में मौजूदा चैंपियन भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच के लिए मैदान में उतरने का निर्देश दिया था। पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीसीबी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता के परिणामों से अवगत कराया, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

गौरतलब है कि पाकिस्तान ने पहले बांग्लादेश के समर्थन में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ समूह चरण के विश्व कप मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया था। बांग्लादेश को आईसीसी द्वारा सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत से बाहर मैच आयोजित करने के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से भी चुनौतीपूर्ण समय में देश के समर्थन पर चर्चा की। आईसीसी और अन्य देशों के साथ चर्चा के बाद, पाकिस्तान सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच खेलने का निर्देश दिया है।

आईसीसी ने रविवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पीसीबी और बीसीबी के साथ बैठक की, जिसमें कोलंबो में भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप 2026 मैच के पाकिस्तान के बहिष्कार के फैसले पर चर्चा की गई। इसके बाद, बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने सोमवार को पाकिस्तान से 15 फरवरी को भारत के खिलाफ आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप मैच खेलने का आग्रह किया।

संक्षिप्त समाचार

थाईलैंड : अनुतिन की पार्टी सबसे आगे लेकिन बहुमत से दूर

बैंकॉक, एजेंसी। थाईलैंड के आम चुनाव में प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नवीराकुल की अगुवाई वाली भुमजैथाई पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन अपने दम पर सरकार बनाना उसके लिए मुश्किल दिख रहा है। शुरुआती नतीजों के मुताबिक, करीब 90 फीसदी मतगणना पूरी होने तक पार्टी को 500 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 195 सीटें मिली हैं।

ओलंपिक विरोध के दौरान हिंसा मेलनी बोलीं–ये इटली के दुश्मन

मिलान, एजेंसी। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलनी ने मिलान विंटर ओलंपिक के विरोध में हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को इटली का दुश्मन करार दिया। शनिवार रात मिलान में लगभग 10,000 लोग आवास और पर्यावरण के मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया स को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा।

वेनेजुएला : राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए जेल पर प्रदर्शन

काराकस, एजेंसी। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में शनिवार को दर्जनों लोगों ने कुख्यात हेलिकॉइड जेल के बाहर प्रदर्शन कर अपने प्रियजनों की रिहाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों में विपक्षी नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के परिजन शामिल थे। हालांकि, सरकार ने पिछले महीने कैदियों को मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन परिवारों ने रिहाई की धीमी गति को लेकर जेल के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने इस जेल को बंद कर सांस्कृतिक केंद्र में बदलने का भी वादा किया है।

कैलिफोर्निया : लोगों पर चढ़ाई कार, बच्चों समेत चार घायल

सैक्रामेंटो, एजेंसी। कैलिफोर्निया के पहाड़ी शहर ट्रकी में शनिवार दोपहर एक 49 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी कार एक किराना भंडार के बाहर खड़े लोगों पर चढ़ा दी। इस घटना में बच्चों सहित चार लोग घायल हो गए, हालांकि उनकी चोटें जानलेवा नहीं हैं। पुलिस का मानना है कि आरोपी ने जानबूझकर पैदल यात्रियों और स्टोर को निशाना बनाया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, जो सैन जोकिन वैली का निवासी बताया जा रहा है।

सैनिकों को कांगो से वापस बुलाएगा दक्षिण अफ्रीका

किंशासा, एजेंसी। दक्षिण अफ्रीका ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के कार्यालय ने बताया कि संसाधनों के पुनर्गठन की आवश्यकता के चलते यह कदम उठाया गया है। दक्षिण अफ्रीका पिछले 27 वर्षों से कांगो में शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है और वर्तमान में उसके 700 से अधिक सैनिक कांगो में तैनात हैं।

बांग्लादेश ने हादी हत्याकांड की जांच में यूएन से मांगी मदद

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय से मदद मांगी है। इंकलाब मोर्चा के प्रवक्ता हादी (32) को चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार दी गई थी। सिंगापुर में इलाज के दौरान हादी की 18 दिसंबर को मौत हो गई थी।

रूस : चाकू हमले में घायल भारतीयों से मिले दूतावास अधिकारी

मास्को, एजेंसी। रूस के एक विश्वविद्यालय में हुए हमले में घायल हुए चार भारतीय मेडिकल छात्रों की हालत स्थिर है। वे तेजी से ठीक हो रहे हैं। कजान के भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने रविवार को चारों छात्रों से अस्पताल में मुलाकात की व उनका हालचाल जाना।

पुतिन से नजदीकी बढ़ाना चाहता था यौन अपराधी एपस्टीन

नए दस्तावेजों से खुलासा, रूस की मदद करने का ऑफर दिया था

वॉशिंगटन डीसी/मॉस्को, एजेंसी। अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट (डीओजे) के नए दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। एपस्टीन ने कई मौकों पर पुतिन और उनके करीबी अधिकारियों तक पहुंच बनाने के प्रयास किए। एपस्टीन 2018 में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के जरिए पुतिन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता था। उसने इसके लिए नॉर्वे के पूर्व पीएम थॉर्बजॉर्न यागलैंड से संपर्क किया था।

जून 2018 के एक ईमेल में एपस्टीन ने नॉर्वे के पूर्व पीएम थोर्ब्योर्न यागलैंड से कहा था कि वह पुतिन को यह सुझाव दें कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव उससे बातचीत करें। दस्तावेजों के मुताबिक, एपस्टीन खुद को एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर पेश कर रहा था, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति और निवेश जैसे मुद्दों पर रूस की मदद कर सकता है।

रूसी राजदूत से मिलता था अपराधी एपस्टीन : सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि एपस्टीन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में रूस के तत्कालीन राजदूत विटाली चुरकिन के साथ नियमित संपर्क में था। विटाली चुरकिन 2006 से 2017 तक संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि रहे। इसी दौरान एपस्टीन की उनसे न्यूयॉर्क में मुलाकातें और बातचीत होती थीं। एपस्टीन ने चुरकिन के बेटे मैक्सिम को न्यूयॉर्क की एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म में नौकरी दिलाने में मदद की पेशकश भी की थी। यह बात एपस्टीन के ईमेल्स में सामने आई है। एपस्टीन ने चुरकिन को लेकर यह भी दावा किया कि वह उसकी बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को बेहतर तरीके से समझने लगे थे। हालांकि दस्तावेजों में इस दावे का कोई सबूत नहीं मिला है। फरवरी 2017 में विटाली चुरकिन की न्यूयॉर्क में अचानक मौत हो गई थी। इसके बाद एपस्टीन ने 2018 के एक ईमेल में लिखा कि अब वह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के जरिए फिर से संपर्क बनाना चाहता है।

2013 से ही पुतिन से मुलाकात की कोशिश कर रहा था : दस्तावेज बताते हैं कि मई 2013 में एपस्टीन ने इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक को ईमेल कर कहा था कि यागलैंड पुतिन से मिलने वाले हैं और उन्होंने पूछा है कि क्या एपस्टीन भी पुतिन से मिल सकता है। एपस्टीन ने दावा किया था कि वह रूस को पश्चिमी देशों से निवेश लेने के तरीकों पर सलाह दे सकता है। एक अन्य ईमेल में उसने कहा कि अगर पुतिन मिलना चाहते हैं तो उन्हें दो से तीन घंटे का समय देना होगा। मई 2013 के ही एक ईमेल में एपस्टीन ने बिना सबूत के यह दावा किया कि उसने सेंट पीटर्सबर्ग में एक आर्थिक सम्मेलन के दौरान पुतिन से मिलने का अनुरोध ठुकरा दिया था। हालांकि दस्तावेजों में यह साफ नहीं है कि पुतिन ने वास्तव में ऐसी कोई मुलाकात चाही थी या नहीं।

पोलैंड में एपस्टीन और रूस के कनेक्शन जांच शुरू : पोलैंड में जेफ्री एपस्टीन के रूस से कथित संबंधों को लेकर जांच शुरू की गई है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि एपस्टीन और रूसी खुफिया एजेंसियों के संभावित रिश्तों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कैबिनेट बैठक में टस्क ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में सामने आ रही जानकारियां इस ओर इशारा करती हैं कि यह यौन शोषण कांड किसी संगठित खुफिया ऑपरेशन का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने इसे पोलैंड की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। रूस ने एपस्टीन के रूसी खुफिया एजेंसियों से जुड़े होने के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि एपस्टीन को लेकर चल रही जासूसी थ्योरी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जेफ्री एपस्टीन न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसर था। उसकी बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज से दोस्ती थी। उस पर 2005 में नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। 2008 में उसे नाबालिग से सेक्स की मांग करने का दोषी ठहराया गया। उसे 13 महीने की जेल हुई। 2019 में जेफ्री को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। लेकिन मुकदमे से पहले ही उसने जेल में आत्महत्या कर ली। उसकी पार्टनर घिसलीन मैक्सवेल को 2021 में उसकी मदद करने के आरोपों में दोषी करार दिया गया।

बांग्लादेश में चुनाव से ठीक पहले जबरदस्त हिंसा, बीएनपी-जमात कार्यकर्ताओं की भिड़त में दर्जनों घायल

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में चुनाव से पहले सड़कों पर भीषण हिंसा की खबरें सामने आई हैं। 12 फरवरी को होने वाले मतदान से मात्र 72 घंटे पहले देश की सड़कें बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं के बीच जंग का अखाड़ा बन गई हैं। रविवार कल रात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़त में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं।

इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक जमात के एक कार्यक्रम में कैश बांटने के आरोपों के बाद दोनों पक्षों में हिंसा हुई है। यह हिंसा तब भड़की जब बीएनपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जमात-ए-इस्लामी पर देर रात एक कार्यक्रम में शामिल लोगों को पैसे बांटने का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक, क्क्हक्ककार्यकर्ता विरोध दर्ज कराने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद जमात ने भी अपने समर्थकों को इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद दोनों गुटों में खूब मारपीट हुई। चुनाव से पहले बढ़ी हिंसा बता दें कि चुनाव की घोषणा के बाद से ही बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। देशभर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं जिनमें कई जगह भारत विरोधी नारेबाजी भी हुई है। पिछले छह हफ्तों में पूरे बांग्लादेश में चुनाव से जुड़ी हिंसा में कई लोग घायल हो चुके हैं।

हसीना की सरकार के पतन के बाद पहला चुनाव : बांग्लादेश में जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद यह पहला चुनाव है। 12 फरवरी के आम चुनाव में सीधा मुकाबला बीएनपी और जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच ही है। ऐसे में ये दोनों गुट चुनाव में पूरी जी जान लगा रहे हैं। जहां एक तरफ बीएनपी के तारिक रहमान ने बांग्लादेश फर्स्ट का नारा दिया है, वहीं जमात को अपने पारम्परिक इस्लामी वोटर्स से उम्मीदें हैं।

'रिहाई के कुछ घंटे बाद ही सहयोगी का अपहरण हुआ'; वेनेजुएला की विपक्षी नेता मचाडो का गंभीर आरोप

काराकास , एजेंसी। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने सोमवार को कहा कि जेल से रिहा होने के कुछ घंटों बाद ही उनके सबसे करीबी सहयोगियों में से एक का अपहरण कर लिया गया। सरकार ने रविवार को नजरबंद विपक्ष के कई प्रमुख सदस्यों को जेल से रिहा कर दिया था। वहीं, मचाडो ने सोशल मीडिया पर कहा कि जुआन पाब्लो गुआनिपा को राजधानी काराकास के एक आवासीय इलाके में आधी रात के आसपास अगवा कर लिया गया था।

मोरक्को में तूफान मार्टा से कम से कम 4 लोगों की मौत : रबात, एजेंसी। मोरक्को में तूफान मार्टा से कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। गौरतलब है कि देश बाढ़ से जूझ रहा है। स्थानीय अधिकारियों ने रविवार को बताया कि उत्तरी मोरक्को में तूफान के कारण आई अचानक बाढ़ में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई। देश में कई दिनों से हो रही भारी बारिश और ओवरफ्लो हो चुके बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। राजधानी रबात से लगभग 270 किलोमीटर उत्तर में स्थित टेटुआन के पास एक गांव में कार के बह जाने से तीन बच्चों (2 से 14 वर्ष की आयु की एक लड़की और दो लड़के) और 30 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति की मौत हो गई। गृह मंत्रालय ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से एक बयान में यह जानकारी दी है। एक अन्य व्यक्ति अभी भी लापता है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि वे इस घटना की जांच शुरू करेंगे। मोरक्को के मौसम विज्ञान महानिदेशालय के हुसैन युआबेद ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि मार्टा नामक तूफान के कारण अचानक बाढ़ आई, जो सप्ताहांत में मोरक्को में पहुंचा और उत्तरी शहरों में 92 मिमी तक बारिश हुई। तूफान मार्टा पड़ोसी देशों स्पेन और पुर्तगाल तक भी पहुंचा।

इस्राइल का वेस्ट बैंक पर कड़ा कदम: बसावट और जमीन पर नियंत्रण बढ़ाया

यरूशलम, एजेंसी। इस्राइल अब वेस्ट बैंक में अपने नियंत्रण को और मजबूत करने और फलस्तीन की सीमित सत्ता को और कमजोर करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए इस्राइल की सुरक्षा कैबिनेट ने रविवार को कई अहम फैसले लिए हैं। वित्त मंत्री बेजल एल स्मोट्रिच के नेतृत्व में कैबिनेट ने जमीन की बिक्री, रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण पर इस्राइली नियंत्रण बढ़ाने का निर्णय लिया। इन फैसलों को लेकर उनका कहना है कि हम फलस्तीनी राज्य की धारणा को दफन करना जारी रखेंगे। माना जा रहा है कि इस्राइल कैबिनेट का यह फैसला फलस्तीनी सत्ता को कमजोर और यहूदी बसावटों के विस्तार को आसान बनाएंगे। हालांकि फलस्तीन और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इसे खतरनाक और अवैध कदम बताया है। इस्राइल विरोधी

संगठन पीस नाउ के शोधकर्ता ने इस फैसले को बहुत महत्वपूर्ण बताया, लेकिन कहा कि इसे लागू करने के लिए वेस्ट बैंक में इस्राइल के शीर्ष कमांडर की मंजूरी भी जरूरी है।

फलस्तीन के राष्ट्रपति ने बताया खतरनाक : फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस निर्णय को खतरनाक और बसावटों को कानूनी रूप देने का खुला प्रयास बताया। उन्होंने अमेरिका और यूएन सुरक्षा परिषद से तुरंत हस्तक्षेप की अपील की। जॉर्डन की विदेश मंत्रालय ने भी इस फैसले की आलोचना की और कहा कि यह अवैध इस्राइली अधिकार थोपने और बसावटों को मजबूत करने का प्रयास है। अब समझिए इस फैसले की अहम बातें वेस्ट बैंक में यहूदी नागरिकों को फलस्तीनी जमीन खरीदने की रोक हटाना। जमीन के रिकॉर्ड सार्वजनिक करना ताकि बसावटें आसानी से बनाई जा सकें। हिब्रोन जैसे संवेदनशील धार्मिक क्षेत्रों में निर्माण की योजना इस्राइली अधिकारियों को सौंपना। पर्यावरण और पुरातात्विक मामलों में इस्राइल को फिलिस्तीनी क्षेत्रों में हस्तक्षेप की अनुमति। एक कमिटी को पुनर्जीवित करना, जो इस्राइल को प्रोएक्टिव तरीके से जमीन खरीदने की अनुमति देगी। बता दें कि वर्तमान में वेस्ट बैंक का 40 प्रतिशत हिस्सा फलस्तीन के नियंत्रण में है, जबकि शेष हिस्सा इस्राइल नियंत्रित है। फलस्तीनियों को निजी तौर पर यहूदी नागरिकों को जमीन बेचने की अनुमति नहीं है। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में 7 लाख से ज्यादा यहूदी रहते हैं। यह क्षेत्र 1967 में इस्राइल ने कब्जा किया था और फलस्तीन इसे भविष्य के राज्य के लिए मांगते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय बसावटों को अवैध मानता है और इसे शांति की राह में बाधा समझता है। हालांकि इससे पहले दिसंबर में इस्राइल की कैबिनेट ने वेस्ट बैंक में 19 नई यहूदी बसावटों को मंजूरी दी थी। जनवरी में यरुशलम के पास एक विवादित बसावट परियोजना का निर्माण शुरू करने का रास्ता भी साफ कर दिया गया, जिससे वेस्ट बैंक आधे में कट जाएगा। यह फैसले फिलिस्तीन के लिए बड़े राजनीतिक और भू-राजनीतिक खतरे को जन्म दे रहे हैं और भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य की संभावनाओं को और कमजोर कर रहे हैं।

कनाडा से रिश्ते बेहतर करने की तैयारी, एनएसए अजीत डोभाल ने कनाडा में उच्च स्तरीय बैठकें की

ओटावा, एजेंसी। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के शासनकाल में भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। अब मौजूदा पीएम मार्क कार्नी की सरकार में फिर से भारत और कनाडा के रिश्तों को बेहतर करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी के तहत भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कनाडा का दौरा किया और वहां ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री की उप सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खुफिया सलाहकार नताली जी. ड्रौइन से मुलाकात की।

दोनों देशों के संबंधों को बेहतर करने की तैयारी : दोनों देशों के संबंधों को फिर से मजबूत करने के प्रयासों की दिशा में यह बातचीत अहम मानी जा रही है। डोभाल ने कनाडा के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, यह बैठक दोनों देशों के बीच नियमित द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता का हिस्सा थी। दोनों पक्षों ने अपने राष्ट्रों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए चल रहीं पहल की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन मामलों पर भविष्य के सहयोग के लिए एक साझा कार्य योजना पर भी सहमति जताई। इस कदम से अधिक व्यावहारिक संयुक्त प्रयासों की राह बनेगी। इस बातचीत में एक अहम निर्णय ये रहा कि दोनों देशों में सुरक्षा और कानून प्रवर्तन संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संचार चैनलों को बेहतर बनाना और नशीली दवाओं की अवैध तस्करी, विशेष रूप से फेंटानिल और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क की गतिविधियों सहित साझा खतरों पर जानकारी का आदान-प्रदान करना है। दोनों अधिकारियों ने साइबर सुरक्षा में सहयोग पर भी सहमति जताई, जिसमें नीतिगत समन्वय और साइबर खतरों पर सूचनाओं का आदान-प्रदान शामिल है। उन्होंने प्रत्येक देश के घरेलू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हुए, धोखाधड़ी की रोकथाम और आव्रजन प्रवर्तन से संबंधित संयुक्त कार्यों पर बातचीत को आगे बढ़ाने का फैसला किया। अजीत डोभाल के इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों में अतीत में आए तनाव के बावजूद व्यावहारिक सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने में दोनों देशों की आपसी रुचि भी स्पष्ट हुई। दो दिवसीय यात्रा के दौरान, डोभाल ने कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। ये मुलाकातें भारत-कनाडा सुरक्षा संबंधों में सकारात्मक गति का संकेत देती हैं, जिनमें मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध जैसी सीमा पार चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

चीन को महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता की गिरफ्तारी मामले में यूएन ने दी चेतावनी

बीजिंग, एजेंसी। चीन में एक महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता की गिरफ्तारी और कथित उत्पीड़न का मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठ गया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने इस पर कड़ी चिंता जताई है। जो चीन गिरफ्तारी और अपनी तानाशाही के लिए पूरे दुनिया में कुख्यात है। उसी चीन को अब उसकी ही चाल भारी पड़ गई है। दरअसल ये देश मानवाधिकार की धज्जियां उड़ानें में प्रसिद्ध है। और अगर कोई आवाज उठाए तो उसके लिए जेल के दरवाजे होते हैं। कुछ ऐसा ही चीन ने एक महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता के साथ किया। लेकिन उकी ये चाल किसी काम नहीं आई। बल्कि जिनपिंग का पासा उलटा पड़ गया। क्योंकि ये मामला अब यून में उठ गया। यूएन ने चीन सरकार को चेतावनी दी है। यूएन ने कहा है कि कार्यकर्ता यांग ली को तुरंत पर्याप्त मेडिकल इलाज और स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति दी जानी चाहिए। विशेषज्ञों ने कार्रवाई को अधिकारों के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को रोकने की कोशिश बताया है।

यूएन विशेषज्ञों के बयान के अनुसार यांग ली को कई बार बीजिंग जाने से रोका गया, जहां वह मेडिकल अपॉइंटमेंट और याचिका प्रक्रिया के लिए जाना चाहती थीं। हर बार रास्ते में रोककर उन्हें हिरासत में लिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मनमानी हिरासत का मामला लगता है। उन्होंने कहा कि यांग ली गंभीर किडनी बीमारी के अंतिम चरण से जूझ रही हैं और उन्हें तत्काल विशेष इलाज की जरूरत है। इलाज से वंचित रखने पर आपत्ति यूएन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा कि बार-बार इलाज से वंचित रखने,

जेल में खराब व्यवहार और लगातार दबाव के कारण उनकी हालत बिगड़ी है। बयान में कहा गया कि पर्याप्त चिकित्सा सुविधा न देना मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। विशेषज्ञों ने चीन से कहा है कि यांग ली और उनके परिवार के खिलाफ डराने और दबाव की कार्रवाई तुरंत बंद की जाए और उन्हें अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज की अनुमति दी जाए। यांग ली जियांगसू प्रांत के जिंतन क्षेत्र की रहने वाली हैं। वह वर्ष 2009 से जमीन अधिग्रहण और फसल हटाने की सरकारी कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं। अपने परिवार और स्थानीय समुदाय की ओर से उन्होंने कई याचिकाएं दायर कीं। यूएन मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार 2014 से उन्हें कई बार प्रशासनिक हिरासत में लिया गया। अक्टूबर 2024 में यांग ली को झगड़ा भड़काने और परेशानी पैदा करने के आरोप में आपराधिक हिरासत में लिया गया। बाद में आरोप बदलकर राज्य संस्थानों के कामकाज में बाधा कर दिया गया। सितंबर 2025 में उन्हें 15 महीने की सजा सुनाई गई। यूएन विशेषज्ञों ने कहा कि मुकदमे की प्रक्रिया में निष्पक्ष सुनवाई से जुड़ी कई खामियां दिखाई दीं। यूएन एजेंसी के अनुसार जेल में किडनी बीमारी के इलाज से वंचित किए जाने के विरोध में यांग ली ने भूख हड़ताल की। इसके बाद उन्हें जबरन नाक के जरिये भोजन दिया गया।

जापान चुनाव में पीएम तकाइची की बड़ी जीत:उनकी पार्टी एलडीपी ने 465 में से 316 सीटें जीतीं; मोदी-ट्रम्प ने बधाई दी

टोक्यो, एजेंसी। जापान में रविवार को हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री साने ताकाइची की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ने बड़ी जीत दर्ज की है। क्क्ष्ट के मुताबिक, एलडीपी के गठबंधन को 465 में से 352 सीटें मिली हैं। एलडीपी अकेले 316 सीटें जीती हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 233 सीटों से काफी ज्यादा हैं। यह पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जा रही है। इससे पहले 1986 में पार्टी ने 300 सीटें जीती थीं। चुनाव जीतने के बाद ताकाइची ने कहा कि वह जापान को मजबूत और समृद्ध बनाने पर काम करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो विपक्ष के साथ मिलकर काम करेंगी। इस जीत के बाद ऊपरी सदन में विपक्ष के नियंत्रण के बावजूद पीएम ताकाइची को कानून पास करने की ताकत मिल गई है। तकाइची की जीत पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने एम्स पोस्ट में लिखा- मुझे विश्वास है आपके कुशल नेतृत्व में हम भारत-जापान मित्रता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी साने ताकाइची को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ताकाइची अपने मजबूत और कंजरवेटिव एजेंडे में सफल हों।

तकाइची ने चीन के खिलाफ रुख मजबूत किया : तकाइची ने चीन के खिलाफ मजबूत रुख अपनाते हुए सैन्य खर्च बढ़ाया है, आर्थिक पैकेज और टैक्स कटौती की घोषणा की है। उन्होंने खाद्य पदार्थों पर 8% सेल्स टैक्स को दो साल के लिए निलंबित करने का वादा किया है ताकि बढ़ती महंगाई से लोगों को राहत मिले। रणनीतिक सलाहकार कंपनी एफजीएस ग्लोबल के मैनेजिंग डायरेक्टर सेइजी इनाडा के मुताबिक, 'अगर तकाइची बड़ी जीत दर्ज करती हैं, तो उन्हें टैक्स में कटौती जैसे अहम फैसलों को लागू करने की आजादी मिलेगी।' ट्रम्प बोले थे- तकाइची शक्तिशाली और बुद्धिमान नेता डोनाल्ड

ट्रम्प ने 5 फरवरी को एक पोस्ट में साने तकाइची को पूर्ण समर्थन दिया है। उन्होंने तकाइची को मजबूत, शक्तिशाली और बुद्धिमान नेता कहा, जो अपने देश से सच्चा प्यार करती हैं और जापान के लोगों को निराश नहीं करेंगी। ट्रम्प ने बताया कि वह 19 मार्च 2026 को व्हाइट हाउस में तकाइची से मुलाकात करेंगे। यह समर्थन जापान के 8 फरवरी 2026 के चुनाव से ठीक दो दिन पहले आया है। यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने जापान के किसी नेता को चुनाव में खुलकर समर्थन दिया है।

सोशल मीडिया पर साने तकाइची का क्रेज बढ़ा : सोशल मीडिया पर साने तकाइची को लेकर 'सानाकात्सु' नाम का ट्रेंड भी चर्चा में है। इसमें उनके इस्तेमाल किए गए सामान, जैसे हैंडबैग और संसद में इस्तेमाल किया जाने वाला गुलाबी पेन, युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गए हैं। एक हालिया सर्वे में 30 साल से कम उम्र के 90% से ज्यादा मतदाताओं ने तकाइची के पक्ष में रुझान दिखाया, हालांकि यह वर्ग आमतौर पर कम मतदान करता है।

लोगों ने बर्फबारी की बीच वोट डाले : रविवार को मतदान के दौरान कई इलाकों में बर्फीले तूफान जैसे हालात रहे। परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, दर्जनों ट्रेन सेवाएं रोकी गईं और 230 घरेलू उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। कई मतदान केंद्रों को समय से पहले बंद करना पड़ा। इसके बावजूद लोग बर्फ और कड़ाके की ठंड में मतदान के लिए पहुंचे। निजी अखबार निक्केई के अनुसार, मतदान खत्म होने से चार घंटे पहले तक टर्नआउट 21.6% रहा, जो 2024 के चुनाव से 2.65 प्रतिशत अंक कम था। पिछले कुछ चुनावों में लोअर हाउस का टर्नआउट करीब 55% के आसपास रहा है। अगर इस बार मतदान और घटता है, तो संगठित वोटिंग ब्लॉक्स का असर और बढ़ सकता है। वोटिंग 289 सिंगल-सीट सीटों पर सीधे मुकाबले से होगी, जबकि बाकी सीटें प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से तय होंगी। तकाइची ने संसद भंग कर चुनाव की घोषणा की थी यह चुनाव इसलिए खास है क्योंकि यह न केवल जापान की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा, आर्थिक नीतियां और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी गहरा असर डालेगा। 2024 के चुनाव में एलडीपी को भारी नुकसान हुआ था और पूर्व प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा की सरकार अल्पमत में आ गई थी। उसके बाद 2025 में एलडीपी की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तकाइची ने जीत हासिल की और जापान इनोवेशन पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर सरकार बनाया।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ्सेट एफपी, 149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अरुणाचल और सिक्किम में लगे भूकंप के झटके, सो रहे लोगों में मचा हड़कंप

-तीव्रता 3.1 मापी गई, भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्वोत्तर भारत के दो राज्यों, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जब लोग रात की गहरी नींद में थे तब जमीन हिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक जान-माल के किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं मिली है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में देर रात करीब 1 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया। अरुणाचल के कुछ घंटों बाद ही सिक्किम के नामची में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 5 बजकर 38 मिनट पर लोग धरती हिलने से जाग गए। यहां भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर केवल 5 किमी की गहराई पर था। बता दें धरती के नीचे होने वाली हलचल ही भूकंप का मुख्य कारण है। हमारी धरती चार परतों से बनी है, जिनके ऊपर टैक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स हर साल अपनी जगह से 4-5 मिमी खिसकती हैं। खिसकने के दौरान जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उससे पैदा होने वाली ऊर्जा ही भूकंप के रूप में सतह को हिला देती है। बता दें भूकंप के झटके महसूस होते ही तुरंत घर से बाहर किसी खुले मैदान में निकल जाएं। यदि बाहर निकलना मुमकिन न हो तो किसी मजबूत मेज या बेड के नीचे छिप जाएं। ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग सीढ़ियों का प्रयोग करें लिफ्ट का इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। बिजली के खंभों, पेड़ों और कांच की खिड़कियों से दूर खड़े हों।

देहरादून में आईएमए के पास विवादित जमीन पर सियासी तकरार तेज

देहरादून (एजेंसी)। देहरादून के धौलास इलाके में इंडियन मिलिट्री एकेडमी (आईएमए) के पास करीब 20 एकड़ जमीन को लेकर नया विवाद उभरा है। इस जमीन को कथित तौर पर एक इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए आवंटित किया गया था। अब बताया जा रहा है कि यह जमीन छोटे-छोटे रिहायशी प्लॉट में बांटी जा रही है, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से खतरा पैदा हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अगर सत्ता में होती तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की दिशा में काम करती। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मामला 2004 का है, जब नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे। उनका तर्क है कि इसके बाद भाजपा कई बार सत्ता में रही और इसे रोक सकती थी। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि यह मामला कांग्रेस की खतरनाक साज़िश को उजागर करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या तिवारी सरकार के दौरान दी गई जमीन हरीश रावत की देख-रेख में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आवंटित थी। चमोली ने यह भी कहा कि अब जमीन पर लैंड माफिया कब्ज़ा कर रहे हैं। विकासनगर सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट विनोद कुमार की शुरुआती जांच में पाया गया कि जमीन को रिहायशी प्लॉट में बदलने से आईएमए की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। जमीन विवाद राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर गरमा गया है। सरकार ने सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है, जबकि कांग्रेस इसे पुराना मामला बताते हुए अपनी जिम्मेदारी कम करती दिख रही है।

रामपुर में अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर, पुलिस फोर्स तैनात

रामपुर (एजेंसी)। शहजादनगर के तहसील सदर क्षेत्र में कृषि भूमि गाटा संख्या 198 पर अवैध रूप से की जा रही प्लाटिंग को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस भूमि के काश्तकारों और कुछ प्लाटिंग एजेंटों ने भूमि को आकर्षक घोषित किए बिना अवैध निर्माण शुरू कर दिया था। भूमि को आकर्षक घोषित करने के लिए उप जिलाधिकारी न्यायालय में शक्कन खां आदि बनाम सरकार के अंतर्गत मामला दायर किया गया था, जिसे तीन नवंबर 2021 को निरस्त कर दिया गया। इसके बावजूद भूमि पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। सिविल लाइंस निवासी इमरान खां ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अवैध निर्माण की शिकायत की। जांच के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान भीड़ जमा हो गई। शहजादनगर थाने की पुलिस ने मौके पर तैनाती कर नियंत्रण किया।

गड्ढे में गिरे युवक के मुंह और नाक में भर गई मिट्टी, दम घुटने से गई जान?

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरने से युवक की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमॉर्टम से जुड़े शुरुआती निष्कर्ष में युवक कमल ध्यानी की मौत का कारण ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया बताया गया है। हालांकि पुलिस सूत्रों ने बताया कि मौत की असल वजह की पुष्टि आधिकारिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कमल ध्यानी बाइक लेकर गड्ढे में गिर गया था। गड्ढे में मौजूद मिट्टी उसके मुंह और नाक में चली गई, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हुई और दम घुट गया। इसके अलावा, छाती पर भारी दबाव के संकेत भी मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि किसी भारी वाहन या वस्तु के गिरने से यह दबाव पड़ा हो सकता है। पोस्टमॉर्टम में मृतक की दाहिनी जांघ पर जलने के निशान भी पाए गए हैं। डॉक्टरों का अनुमान है कि यह निशान बाइक के साइलेंसर के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण बने होंगे। डॉक्टरों का कहना है कि यह मामला दुर्घटनावश मौत का प्रतीत होता है, लेकिन मौत के समय और तरीके को लेकर अंतिम राय गहन जांच के बाद ही दी जाएगी। इस बीच, जांच में यह भी सामने आया है कि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से सीवर लाइन बिछाने का ठेका पाने वाली निजी कंपनी के मैनेजर को हादसे की जानकारी थी, लेकिन उसने भी पुलिस या अन्य सरकारी एजेंसियों को इसकी सूचना नहीं दी। जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक वह इस मामले में हादसे की जानकारी रखने वाला छठा व्यक्ति था। पुलिस पहले ही ठेकेदार हिमांशु गुप्ता, सब-कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार प्रजापति, मजदूर योगेश, सुरक्षा गार्ड देशराज और राहगीर विपिन सिंह की भूमिका की पहचान कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक एक फोन कॉल में प्रजापति ने कंपनी के डायरेक्टर हिमांशु और प्रोजेक्ट मैनेजर को हादसे की जानकारी दी थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को सूचना नहीं दी गई। इस मामले में राजेश कुमार, प्रजापति और योगेश को गिरफ्तार किया जा चुका है।

वीर सावरकर को यदि दिया गया भारत रत्न तो इससे सम्मान की गरिमा होगी कम : भाई जगताप

-संघ प्रमुख के बयान को लेकर सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली (एजेंसी)। संघ प्रमुख द्वारा वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता भाई जगताप ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा, कि जिन व्यक्तियों पर गंभीर आरोप रहे हों, उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान देना भारत रत्न की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा होगा।

भाई जगताप ने कहा कि भारत रत्न केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं से जुड़ा सम्मान है। उन्होंने कहा कि अब तक यह सम्मान उन्हीं महान व्यक्तित्वों को दिया गया है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र या किसी बड़े सामाजिक उद्देश्य के लिए समर्पित किया। ऐसे में विवादित नामों को इस श्रेणी में शामिल करना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न से बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। संघ प्रमुख किसी संगठन के प्रमुख हैं, पूरे देश के नहीं। वीर सावरकर को लेकर समाज में मतभेद और गंभीर आरोप मौजूद हैं, ऐसे में उन्हें यह सम्मान देना पूरे देश में बहस और सवाल खड़े करेगा। भाई जगताप ने कहा कि यदि इस तरह के नामों को भारत रत्न दिया जाता है, तो सम्मान की

प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा और देश इसका मूल्यांकन करेगा।

मौजूदा सरकार में कई दागी मंत्री

केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मौजूदा सरकार में ऐसे कई मंत्री हैं, जिन पर दाग होने की बातें सामने आती रही हैं। ऐसे माहौल में भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान पर फैसला लेना बेहद संवेदनशील मामला है। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को बेवजह हवा नहीं देना चाहते, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार को लेना होगा और जनता अपना जवाब जरूर देगी।

संघ प्रमुख के एक कार्यक्रम में अभिनेता की मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देते हुए भाई जगताप ने कहा कि खेल और कला को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। उन्होंने देश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि संसद देश का पवित्र मंदिर है, लेकिन विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अवसर नहीं दिया जाता। चीन जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए, न कि उन्हें दबाने का प्रयास करना चाहिए।

तीन बच्चों वाला बयान हास्यास्पद

संघ प्रमुख के तीन बच्चों वाले बयान को लेकर भाई जगताप ने इसे हास्यास्पद करार दिया। उन्होंने कहा कि जब भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तब इस तरह की सलाह देना गैर-जिम्मेदाराना है। आज महिलाएं पहले से ज्यादा असुरक्षित हैं और युवा खुद यह तय करने में सक्षम हैं कि उन्हें कब और किससे विवाह करना है।

संसद में चर्चा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण

अन्य राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए भाई जगताप ने कहा कि केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, यदि कोई मामला है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने संसद के कामकाज पर भी सवाल उठाए और कहा कि संसद देश का पवित्र मंदिर है, लेकिन विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अवसर नहीं दिया जाता। चीन जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए, न कि उन्हें दबाने का प्रयास करना चाहिए।

मनी लॉन्ड्रिंग मामला : एसआईटी ने तेज की जांच टीना अंबानी को जल्द मिलेगा ईडी का नया समन

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच में शामिल होने के लिए जल्द ही नया समन जारी करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले सोमवार को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुईं। सूत्रों के अनुसार, अब उन्हें दोबारा बुलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यह पूरी कार्रवाई अनिल अंबानी और उनके व्यापारिक समूह से जुड़े 40,000 करोड़ रुपये के कथित बैंकिंग और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामले से संबंधित है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। यह एसआईटी फेडरल जांच एजेंसी की हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेशन यूनिट के तहत काम कर रही है, जिसका नेतृत्व एडिशनल डायरेक्टर रैंक के एक

अधिकारी कर रहे हैं। इस टीम में लगभग आधा दर्जन अनुभवी जांचकर्ता शामिल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते अनिल अंबानी समूह के खिलाफ चल रहे मामलों की समीक्षा के बाद यह निर्देश दिया था कि एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीम बनाई जाए। जांच एजेंसी पिछले एक साल से इस समूह की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। अब तक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तीन प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी हैं, जो पुलिस की प्राथमिकी के समान होती हैं। अब तक की कार्रवाई में जांच एजेंसी ने लगभग 12,000 करोड़ रुपये की संपत्ति भी अटैच की है। सूत्रों का कहना है कि नवनियुक्त एसआईटी आने वाले दिनों में समूह की कंपनियों और उनके अधिकारियों द्वारा किए गए संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की गहराई से पड़ताल करेगी। इस दौरान कई अन्य नई रिपोर्ट दर्ज होने की भी संभावना है, जिससे अंबानी परिवार और उनके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

पक्षियों को दाना खिलाना पड़ा महंगा, बुजुर्ग महिला पर लगा 2.27 लाख का जुर्माना

मुंबई (एजेंसी)। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी खबर तेजी से सुर्खियां बटोर रही है, जिसने पशु-पक्षियों के प्रति प्रेम और देश के कड़े कानूनों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। मामला सिंगापुर का है, जहां एक 71 साल की बुजुर्ग महिला को बार-बार जंगली पक्षियों, विशेषकर कबूतरों को दाना खिलाने के कारण भारी-भरकम आर्थिक दंड भुगतना पड़ा है। यह खबर जैसे ही सार्वजनिक हुई, इंटरनेट पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आने लगीं। जहां कुछ लोग इसे कानून की अति मान रहे हैं, वहीं कई लोग सार्वजनिक स्वच्छता और नियमों के पालन के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं।

पूरा मामला सिंगापुर की निवासी सन्मुगमनाथन शमला से जुड़ा है।

अदालत ने उन पर 3,200 सिंगापुर डॉलर, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 2 लाख 27 हजार रुपये होते हैं, का जुर्माना लगाया है। महिला पर यह कार्रवाई वाइल्डलाइफ एक्ट के उल्लंघन के तहत की गई है। रिपोर्टों के अनुसार, महिला ने अदालत में अपने ऊपर लगे चार आरोपों को स्वीकार कर लिया, जबकि इसी तरह की पांच अन्य घटनाओं को भी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान संज्ञान में लिया गया। प्रशासन का तर्क है कि जंगली पक्षियों को इस तरह दाना खिलाने से न केवल इलाके में गंदगी फैलती है, बल्कि इससे पारिस्थितिक संतुलन भी बिगड़ता है और पक्षियों की आबादी अनियंत्रित रूप से बढ़ सकती है। हैरानी की बात यह है कि यह महिला के खिलाफ की गई पहली कार्रवाई नहीं थी। इससे पहले मई 2025 में भी उन्हें इसी कृत्य के लिए 1,200 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना भरना पड़ा था। उस दौरान महिला ने अदालत में भविष्य में ऐसा न करने का लिखित वादा भी किया था। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड और सबूतों के अनुसार, उन्होंने अपने वादे को दरकिनार करते हुए महज एक महीने के भीतर फिर से पक्षियों को दाना खिलाना शुरू कर दिया।

ओवैसी ही बीजेपी के असली लाइफलाइन, भगवान राम से ज्यादा ओवैसी का नाम लेते हैं

तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला

हैदराबाद (एजेंसी)। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भगवान राम से भी ज्यादा अहमियत देती है और चुनाव जीतने के लिए ओवैसी का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी ही बीजेपी के असली लाइफलाइन हैं। रेड्डी ने कहा कि यह बीजेपी का इतिहास है। अगर आप इसे एनालाइज करें, तो उनके लिए सिर्फ एक ही भगवान हैं, असदुद्दीन ओवैसी। वे यूं ही भगवान राम का नाम लेते हैं, लेकिन वे हर दिन जिसके आगे झुकते हैं, वह असदुद्दीन ओवैसी हैं। उनकी लाइफलाइन असदुद्दीन ओवैसी हैं। देखिए वे कितनी बार राम को याद करते हैं और कितनी बार ओवैसी का नाम लेते हैं। इसकी पड़ताल होनी चाहिए।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी ओवैसी को अलादीन के चिराग की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि हर बार वे ओवैसी को अलादीन का जादुई चिराग बनाकर वोट मांगते हैं। आखिर सरकार तो आपकी ही है ना? अगर ओवैसी इतने विलेन हैं, तो आप उन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? रेड्डी ने एआईएमआईएम की निंदा के लिए भी बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में एआईएमआईएम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो चुनाव लड़ती है। जहां वे जीतते हैं, जीतते हैं। जहां वे हारते हैं, हारते हैं। उन्होंने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहां तक ??कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ा, जहां उन्होंने पांच सीटें जीतीं हैं। वे भी एक पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन आप कब तक उनके नाम पर वोट मांगते रहेंगे? धार्मिक नफरत भड़काकर, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को राक्षस बताकर और उसके जरिए पॉलिटिकल रूप से जिंदा रहने की कोशिश करना आइडियोलॉजिकल गरीबी की हद है। तेलंगाना के लोगों को सोच समझ कर वोट देना चाहिए।

एसआईआर के दौरान हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, डीजीपी से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

-पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकियों का मामला

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ड्यूटी के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ कथित हिंसा और धमकियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, चुनाव आयोग द्वारा दाखिल हलफनामे पर जवाब न देने को लेकर डीजीपी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

अदालत ने यह निर्देश उस समय दिया, जब केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने पीठ का ध्यान चुनाव आयोग के हलफनामे की ओर दिलाया। इस हलफनामे में पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गंभीर अनियमितताओं, धमकियों और हिंसा के आरोप लगाए गए हैं। आयोग ने दावा किया है कि राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में भय और दबाव का माहौल कहीं अधिक है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। सुनवाई के

दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में डराने-धमकाने, बाधा डालने और भ्रामक सूचनाएं फैलाने की घटनाएं सामने आई हैं। हलफनामे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी भड़काऊ भाषण देने और भय का वातावरण बनाने के आरोप लगाए गए हैं। आयोग का कहना है कि इस तरह के बयानों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।

चुनाव आयोग ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया है कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जलाए गए। इसके अलावा, पंचायत भवनों में सुनवाई के लिए पहुंचे बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के साथ हिंसा की घटनाएं हुईं। आयोग के अनुसार, कई अधिकारियों को लोकतांत्रिक दायित्व निभाते समय अपनी जान का खतरा महसूस हुआ, जिससे वे भय के साए में काम करने को मजबूर हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को गंभीर मानते हुए राज्य पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि चुनाव जैसी संवैधानिक प्रक्रिया में लगे अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है। यदि इस दायित्व में चूक हुई है, तो इसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

पीठ ने स्पष्ट किया कि डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से यह बताना होगा कि चुनाव आयोग के आरोपों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए। अदालत ने संकेत दिए कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे और सख्त निर्देश भी दिए जा सकते हैं। अब इस मामले में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के जवाब पर सबकी नजर टिकी हुई है।

सुकमा में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 51 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षाबलों को एक बड़ी दोहरी सफलता हाथ लगी है। सोमवार को एक विशेष अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने न केवल नक्सलियों के एक गुप्त ठिकाने का भंडाफोड़ किया, बल्कि भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी जब्त की। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, रायगुडेम गांव के पास स्थित पहाड़ी जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और स्थानीय पुलिस की एक संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षाबलों ने 65 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल) सेल और कमर पर बांधी जाने वाली दो विशेष थैली बरामद कीं। इतनी बड़ी संख्या में बीजीएल सेल की बरामदगी को सुरक्षाबल नक्सलियों की किसी बड़ी और घातक साजिश की विफलता के रूप में देख रहे हैं।

इस सैन्य सफलता के साथ-साथ

बस्तर संभाग में एक ऐतिहासिक रणनीतिक कामयाबी भी देखने को मिली है। सुकमा और बीजापुर जिलों में कुल 51 सक्रिय नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता त्याग कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों पर सामूहिक रूप से 1.61 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

अधिकारियों का मानना है कि नक्सलियों के इस सामूहिक आत्मसमर्पण के पीछे हाल ही में शीर्ष नक्सली नेता एल. प्रभाकर राव का खात्मा एक बड़ा कारण रहा है। अबूझमाड़ के जंगलों में हुई मुठभेड़ में प्रभाकर राव और उसके छह साथियों के मारे जाने के बाद नक्सलियों का मनोबल बुरी तरह टूट गया है। राव को एक खतरनाक एंबुश रणनीतिकार माना जाता था, जिसकी मौत ने नक्सली संगठन के ढांचे को कमजोर कर दिया है। बस्तर रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में 2,400 से अधिक नक्सली हथियार डाल चुके हैं। सरकार की पूना मारगेम (नई राह) और नियद नेल्लानार (आपका अच्छा गांव) जैसी पुनर्वास योजनाओं का जमीनी स्तर पर सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। इन पहलों के माध्यम से प्रशासन अब उन दुर्गम इलाकों तक सीधी पहुंच बना रहा है, जहाँ कभी नक्सलियों का दबदबा हुआ करता था। फिलहाल, सुरक्षाबलों ने इलाके में चौकसी और अधिक बढ़ा दी है और आसपास के जंगलों में गहन तलाशी अभियान जारी है ताकि बचे हुए नक्सलियों पर दबाव बनाया जा सके।

12 फरवरी को 35 साल बाद बांग्लादेश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा... भारत की पैनी नजर

नई दिल्ली (एजेंसी)। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को संसदीय चुनाव होने वाले हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने और खालिदा जिया के निधन के बाद यह पहला चुनाव है। 1991 से 2024 तक बांग्लादेश की राजनीति में इन दो नेताओं का दबदबा रहा। इसके बाद 35 साल बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि 2024 में हुए छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में पार्टी की भूमिका की वजह से यह फैसला लिया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि बांग्लादेश के ये चुनाव सिर्फ देश की राजनीति ही नहीं, बल्कि पूरे साउथ एशिया की डिप्लोमेसी और पावर बैलेंस को बदल सकते हैं। इसलिए भारत, पाकिस्तान और चीन भी इन चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश की विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया है। भारत के साथ रिश्ते अब अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर हुए हैं और चीन के साथ रणनीतिक रिश्ते और मजबूत हुए हैं। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, मंदिर तोड़ने और हिंसा की खबरें आने लगीं, जिस पर भारत ने चिंता जाहिर है। बांग्लादेशी सोशल मीडिया पर ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर भड़काऊ बातें फैलीं।

भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर पर बीएसएफ और बीजीबी के बीच तनाव बढ़ा, तस्करी और बाड़ को लेकर बहस हुई। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हिंसा फैली और भारत के खिलाफ माहौल बना। दोनों देशों के बड़े नेताओं और अधिकारियों ने आपस में सीधे बात करना शुरू किया, इससे पुराने तनाव धीरे-धीरे कम होने लगे। 2025 में कराची और चटगांव के बीच कॉर्गो जहाज फिर से चलने लगे, जिससे समुद्री व्यापार आसान हुआ। 2026 की शुरुआत में ढाका और कराची के बीच कई साल बाद सीधी फ्लाइट्स शुरू हुईं। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने वीजा के नियम आसान करने पर बात की, खासकर सरकारी काम से आने-जाने वालों के लिए। अंतरराष्ट्रीय बैठकों में पाकिस्तान और बांग्लादेश कई मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ खड़े नजर आए, जिससे तालमेल बढ़ा।

चीन से और करीबी बढ़ी

2025 में बांग्लादेश के नेताओं और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, जिसमें रिश्तों को और आगे बढ़ाने पर खुलकर बात हुई। दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और निवेश से जुड़े समझौतों पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया। चीन ने बांग्लादेश से आने वाले ज्यादातर सामान पर टैक्स नहीं लगाने की सुविधा आगे भी जारी रखने की बात कही। रक्षा के मामले में भी दोनों देश करीब आए और ड्रोन व दूसरी सैन्य तकनीक से जुड़े समझौते किए गए। बांग्लादेश का आम चुनाव तय करेगा कि देश आगे भारत के करीब रहेगा या पाकिस्तान और चीन की तरफ झुकेगा। इससे साउथ एशिया का पावर बैलेंस बदल सकता है। इसी वजह से इस चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है। बांग्लादेश, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग चारों तरफ से घेरता है। भारत का नॉर्थ-ईस्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए भारत से कनेक्ट होता है। इसके बाद बांग्लादेश की भूमिका भारत के लिए कनेक्टिविटी, सुरक्षा और सप्लाई लाइनों के लिहाज से बेहद संवेदनशील हो जाती है।

दूसरी बड़ी वजह है भारत-चीन की रणनीतिक खींचतान। चीन पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में बंदरगाह, सड़क, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर चुका है। बांग्लादेश अगर चीन के ज्यादा करीब जाता है, तब यह भारत के लिए सीधा रणनीतिक झटका होता है, खासकर बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन रीजन में। बांग्लादेश की समुद्री सीमा इस इलाके को रणनीतिक रूप से बहुत अहम बना देती है। यह इलाका ग्लोबल शिपिंग, एनर्जी रूट्स और नौसैनिक गतिविधियों के लिए बेहद संवेदनशील है।